रांची, गुरुवार
26.11.2026
वर्ष : 11, अंक : 351, पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरे हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस 2026

एवं सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर

स्थापना दिवस परवाड़ा

15 से 28 नवम्बर, 2026



मेला-सह-प्रदर्शनी
विभागीय स्टॉल में जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं उपयोगी सेवाओं की विस्तृत जानकारी



जिला पवेलियन
हर जिले के विशिष्ट उत्पाद, पर्यटन और आर्थिक झलक साथ ही, राज्य स्तरीय मंच पर जिला स्तर के चयनित प्रतिभागियों का प्रतिभा प्रदर्शन

प्रवेश निःशुल्क

26 से 28 नवम्बर 2026
तक खेलगांव, राँची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है



फ़ूड कोर्ट
धुस्का-घुघनी, पीठा, छिलका रोटी और असली झारखण्डी स्वाद

जन-जन की भागीदारी
झारखण्ड की खुशहाली



सांस्कृतिक संध्या
राज्य की समृद्ध कला, लोक संगीत और मनमोहक पारंपरिक नृत्यों की भव्य प्रस्तुतियाँ

उद्घाटन समारोह

गरिमामयी उपस्थिति

श्री दीपक बिरुवा
माननीय मंत्री, राजस्व, भूमि सुधार विभाग एवं परिवहन विभाग

श्री संजय प्रसाद यादव
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग

दिनांक: **26 नवम्बर, 2026** | समय: **संध्या 05 बजे से**
स्थान: **खेलगांव, राँची**



आइए, हम सब मिलकर इस उत्सव के साक्षी बनें

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

स्थापना दिवस पखवाड़े में विकास कार्यों को मिली गति, बढ़ी जनभागीदारी

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा-2026 के तहत बुधवार को राज्यभर में रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की पहल पर पंचायतों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हजारों लोगों ने भागीदारी निभाई। जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने पर विशेष जोर रहा।



आवास योजनाओं के तहत पाकुड़ में 53, सरायकेला-खरसावां में 61, सिमडेगा में 34 और गोड्डा में 22 परिवारों ने नवनिर्मित घरों में गृह प्रवेश किया। सिमडेगा में ग्रामीण रोजगार के तहत 8,408 मजदूरों को काम उपलब्ध कराने और 4,822 मानव दिवस सृजित करने की जानकारी दी गई। जिले की 94 पंचायतों में ग्रामसभाएं आयोजित कर विकास योजनाओं के लिए 457 आवेदन प्राप्त किए गए।

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जिलों में क्विज, निबंध, पेंटिंग, नृत्य, गायन और नाटक प्रतियोगिताओं के जरिए विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिला। वहीं, नशामुक्ति, बाल विवाह, बाल श्रम और महिला स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। रामगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 17,326 लोगों की सहभागिता दर्ज की गई।

इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, मलेरिया जांच, रक्तदान, कृषि प्रशिक्षण, बीज वितरण, जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार जैसी पहल भी हुईं। स्थापना दिवस पखवाड़े की गतिविधियों ने ग्रामीण विकास, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को नई गति दी। इस अवसर पर ग्रामीण सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

ठंड को देखते हुए श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की समय-सारणी में बदलाव

रांची : संत शिरोमणि सदानंद महाराज जी के सानिध्य में एम.आर.एस. श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित पुंदाग स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की समय-सारणी में गोपाष्टमी के बाद परिवर्तन किया गया है। ठंड के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के खुलने और बंद होने का नया समय निर्धारित किया गया है। ट्रस्ट के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय सर्राफ ने बताया कि नई समय-सारणी के अनुसार अब मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलेगा और दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन-पूजन के लिए खुला रहेगा। दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद मंदिर दोपहर 3 बजे पुनः खुलेगा और श्रद्धालु शाम 8 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि संध्या आरती प्रतिदिन शाम 5:30 बजे होगी। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित अरविंद पांडेय 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और मंदिर के सभी पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा विधिवत संपन्न कराए जाएंगे।

बच्चों के धरने के दो दिन बाद ही सरयू राय ने शुरू कराया सड़क निर्माण

बिभा संवाददाता



जमशेदपुर। जर्जर सड़क से परेशान स्कूली बच्चों के धरने का असर महज दो दिनों में दिखा। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की पहल पर मानगो नगर निगम के वार्ड संख्या 23 अंतर्गत आजादनगर रोड नंबर-5 की मल्लिक कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया। डॉ. अयूब खान के घर से भैया पान दुकान तक बनने वाली इस सड़क का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है।

गौरतलब है कि दो दिन पूर्व रविवार को सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान स्थानीय बच्चे धरने पर बैठ गए थे। बच्चों का कहना था कि जर्जर सड़क के कारण उन्हें स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती है। उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, वे प्रत्येक रविवार को धरना जारी रखेंगे।बच्चों के धरने की जानकारी मिलते ही विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को बताया कि सड़क निर्माण की अनुशंसा वे दो माह पूर्व ही अपनी विधायक निधि से कर चुके हैं तथा अगले दो दिनों में काम शुरू हो जाएगा। विधायक के आश्वासन के अनुरूप बुधवार को सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया।

सड़क निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लड्डू वितरित किए। वार्ड संख्या 23 की पार्षद होमा आफरीन सहित स्थानीय नागरिकों ने विधायक सरयू राय के प्रति आभार जताया।

इस अवसर पर मानगो नगर निगम जनसुविधा समिति के संयोजक पप्पू सिंह, वार्ड संख्या 23 की पार्षद होमा आफरीन, वार्ड संख्या 28 की पार्षद जेबा फरीन, वार्ड संख्या 21 की पार्षद इरफाना खातून, वार्ड संख्या 24 के पार्षद नुरूल हक अंसारी, पिंटू सिंह, आफताब अहमद सिद्दीकी, फिरोज आलम, सन्नी मिर्जा, मुकेश सिंह सहित अनेक स्थानीय लोग उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत बेड़ो में रक्तदान शिविर का आयोजन

बेड़ो (रांची)(बिभा): झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत बेड़ो प्रखंड कार्यालय परिसर में रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन झारखंड राज्य आजीविका मिशन (जेएसएलपीएस) एवं प्रखंड कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से किया गया। शिविर में सदर अस्पताल, रांची से विशेष चिकित्सा टीम को आमंत्रित किया गया था। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस अभिषेक चंद के मार्गदर्शन एवं सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।



शिविर में रक्तदान के साथ-साथ लोगों के ब्लड प्रेशर (बीपी), शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच भी की गई। इस दौरान दो भाइयों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इनमें रोजगार सेवक शाहब हजमा एवं किसान छोटू मुंडा शामिल हैं। दोनों ने रक्तदान कर दूसरों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संजय तुर्की, सहायक अभियंता पटेल, रोजगार सेवकों, जेएसएलपीएस के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक मुकेश कुमार सिन्हा, एफटीसी कालेश्वर गोप, मनोरंजन महतो, अरविंद खलखो, गोविंद खलखो, कुलदीप एंथोनी खलखो, कुलदीप, अनिल पहन एवं बिरजू बांडो का सराहनीय योगदान रहा।

श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वार्षिक समारोह 2026 का भव्य आयोजन



जमशेदपुर(बिभा): श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बी.एड. एवं डी.एल.एड. सत्र 2024-2026 का वार्षिक समारोह 25 नवंबर 2026 को हर्षोल्लास, उमंग एवं उत्सवपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस समारोह का उद्देश्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियों, प्रतिभाओं, समर्पण एवं सर्वांगीण विकास को सम्मानित करना तथा उनकी सराहना करना था समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रतिष्ठित उपाधियों एवं सम्मान से विद्यार्थियों को सम्मानित विद्यार्थियों के उत्कृष्ट गुणों, शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें विभिन्न उपाधियाँ प्रदान की गईं, इनमें बी.एड. वर्ग में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का खिताब प्रिया ठाकुर तथा डी.एल.एड. वर्ग में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का खिताब सिद्धि कुमारी को प्रदान किया गया। अन्य सम्मानित विद्यार्थियों में 'ऑरा ऑन स्टेज' का खिताब अर्पिता ग्रेसी लवलेस, 'मिस्टर ओबीडिएंट' बुधराम मुंडा, 'मिस हार्मनी' अनामिका झा, 'मिस डायनामिक' प्रिया जोंको, 'मोस्ट डिसिप्लिन्ड' बंदना महतो, 'मिस स्टूडियस' प्रियंका प्रधान, 'स्टार परफॉर्मर' यतिश्री प्रधान तथा 'बेस्ट प्लेयर' का खिताब हेमंत महतो को प्रदान किया गया। इस अवसर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण कॉलेज की वार्षिक पत्रिका श्रीवाणी' के आठवें संस्करण का लोकार्पण रहा। इस अवसर ने समारोह की गरिमा को और भी बढ़ा दिया।

दार्जिलिंग और मिरिक के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुए वर्कर्स कॉलेज के विद्यार्थी

जमशेदपुर(बिभा): जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के भूगोल विभाग की ओर से स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और मिरिक का पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण बुधवार को शुरू हुआ. इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है. भ्रमण को रवाना करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ विषय की व्यावहारिक समझ को मजबूत बनाते हैं. भ्रमण का नेतृत्व कर रहे भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार चौबे ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थी क्षेत्र की भू-आकृतिक, भौतिक एवं पारिस्थितिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही स्थानीय कृषि, आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन की संभावनाओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनशैली का भी अवलोकन करेंगे.वहीं, भ्रमण में शामिल सहायक प्राध्यापिका शोभा मुवाल ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर विद्यार्थी अपना शोध प्रबंध तैयार करेंगे. उन्होंने कहा कि यह भ्रमण विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उनकी शोध क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

अवैध अफीम की खेती पर रोक के लिए रांची प्रशासन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

बिभा संवाददाता

रांची: जिले में अफीम की अवैध खेती पर प्रभावी रोकथाम और लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन ने मोरहाबादी मैदान से संयुक्त रूप से 8 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



ये वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों को अफीम की अवैध खेती से होने वाले सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय नुकसान तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। अभियान के जरिए लोगों से अफीम की खेती और इसके अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील की जाएगी।

अभियान के तहत बताया जाएगा कि अफीम की खेती करना या इसके लिए जमीन उपलब्ध कराना एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 20 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास व जुमार्ने का प्रावधान है। प्रशासन ने अपील की है कि अधिक मुनाफे के लालच में न तो खुद अफीम उपजाएं और न ही किसी को लीज या पट्टे पर जमीन दें। साथ ही अवैध खेती की सूचना पुलिस-प्रशासन को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सूचना देने वालों का नाम-पता व पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

लोगों को यह भी जानकारी दी जाएगी कि अवैध खेती व कारोबार में संलिप्त तथा आरोप पत्रित लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे और अवैध कमाई से अर्जित धन व संपत्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसके अलावा परिवहन व खरीद-बिक्री में शामिल क्रेता-विक्रेताओं पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता अभियान में बताया जाएगा कि अफीम की खेती से जमीन की उर्वरता घटती है और तालाब, नदी व कुएं जैसे जल स्रोत प्रदूषित होने का खतरा रहता है। इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और नशे की लत से विशेषकर युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। इस मौके पर ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय, डीएसपी मुख्यालय-1 अमर पांडेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सीएसआईआर-एनएमएल का 77वां स्थापना दिवस आज, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि

बिभा संवाददाता



जमशेदपुर: सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल), जमशेदपुर का 77वां स्थापना दिवस समारोह 26 नवंबर (गुरुवार) को आयोजित किया जाएगा। समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि और अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जे. डी. पाटिल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधुरी के नेतृत्व में किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रयोगशाला की आधारशिला 21 नवंबर 1946 को सी. राजगोपालाचारी ने रखी थी, जबकि 26 नवंबर 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका औपचारिक उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया था। सर शांतिस्वरूप भटनागर की परिकल्पना और टाटा समूह व सर इंदर सिंह के सहयोग से स्थापित इस संस्थान को इसके प्रथम भारतीय निदेशक डॉ. बलराज निज्हावन ने मजबूत आधार दिया।

वर्तमान में सीएसआईआर-एनएमएल खनिज प्रसंस्करण, महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण, अपशिष्ट से संसाधन पुनर्प्राप्ति और उन्नत पदार्थ विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संस्थान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, इस्पात और इसरो व टाटा स्टील जैसे प्रमुख संगठनों को तकनीकी समाधान व अनुसंधान सहयोग प्रदान कर रहा है। स्थापना दिवस समारोह के जरिए संस्थान अपनी 77 वर्षों की वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा।

70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आगाज आज, मुख्य अतिथि डॉ. महुआ माजी करेंगी उद्घाटन

बिभा संवाददाता

रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 (अंडर-19 बालक-बालिका ताइक्वांडो) का उद्घाटन 26 नवंबर को खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होगा। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी होंगी, जिनके साथ विभिन्न खेल संगठनों के विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे।



26 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 39 राज्यों एवं खेल इकाइयों की टीमों के कुल 701 खिलाड़ी (339 बालक व 362 बालिका) तथा 150 कोच एवं मैनेजर शामिल हो रहे हैं। अब तक 30 बालक व 30 बालिका टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और शेष टीमों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की फील्ड ऑफिसर मुक्ता बब्बर के नेतृत्व में खिलाड़ियों के दस्तावेज जांच के साथ अंगूठे व रेटिना का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है।

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि सभी मुकाबले गणपत राय इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों व टीम पदाधिकारियों के लिए आवासन, भोजन और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है तथा आयोजन के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला उद्यान विकास योजना के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न, प्रशिक्षित लाभुकों को मिला प्रमाण पत्र

बिभा संवाददाता

बेड़ो: जिला उद्यान विकास योजना के तहत उद्यान विभाग की ओर से आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार, 25 नवंबर को बेड़ो प्रखंड के बिशु भगत महिला महाविद्यालय के सभागार में समापन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बेड़ो प्रखंड के उप प्रमुख मुदस्सिर हक एवं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर करमा उरांव की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप प्रमुख मुदस्सिर हक एवं प्रोफेसर करमा उरांव उपस्थित थे। वहीं माइनॉरिटी समग्र विकास संस्था, रांची के सचिव अब्दुल कलाम ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

यह पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उद्यान कार्यालय, रांची के सौजन्य से उद्यान विभाग द्वारा माइनॉरिटी समग्र विकास संस्था, रांची के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान लाभुकों को उद्यानिकी खेती से संबंधित जानकारी एवं विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

समापन समारोह में अतिथियों ने प्रशिक्षित लाभुकों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से किसानों एवं ग्रामीण लाभुकों को बागवानी और उद्यानिकी खेती के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाकर वे अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षित लाभुकों को शुभकामनाएं दी गईं।

डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन, 190 मॉडलों में दिखी विद्यार्थियों की प्रतिभा

बिभा संवाददाता

बेड़ो (रांची): विनय बगीचा स्थित डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, बेड़ो में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार का परिचय देते हुए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुल 190 आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए।



प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें वर्षा संसूचक, स्वस्थ एवं अस्वस्थ भोजन परियोजना, जल के स्रोत, गुरुत्वाकर्षण बैटरी, बारकोड रीडर, कचरा पृथक्करण यंत्र, बिना बिजली का फ्रिज, स्वचालित औषधि यंत्र, 2037 में जल संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चक्रवात अर्णव प्रमुख रहे।

इसके अलावा आदिवासी गांव, भू-आकृतियां, स्मार्ट गांव, प्रदूषण, घरों एवं ऋतुओं के प्रकार, सड़क सुरक्षा, समुद्री डाकुओं का जहाज, जल के उपयोग तथा दिन और रात जैसे विषयों पर भी आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों के मॉडलों में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता की झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बेड़ो की मुखिया सुशांति भगत, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार, महासचिव मोजाहिदुल इस्लाम, कोषाध्यक्ष आलोक बिपिन टोप्पो, पंचायत समिति सदस्य राखी भगत, पुरियो पंचायत के मुखिया नीरज कुजूर, विद्यालय के संस्थापक विष्णु महतो एवं सचिव श्रवण महतो उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन किया और उनकी प्रतिभा एवं मेहनत की सराहना की।

मुखिया सुशांति भगत ने कहा कि बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल उनकी प्रतिभा और रचनात्मक सोच को दर्शाते हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वे क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं।

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों के सर्वांगीण विकास और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने का बेहतरीन माध्यम है। सीमित संसाधनों में विद्यार्थियों ने जिस तरह के मॉडल तैयार किए हैं, वे सराहनीय हैं।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश कुमार ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास विकसित करना है। ऐसे आयोजनों से बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझकर उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं।

तुको में अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर

बिभा संवाददाता

बेड़ो: थाना क्षेत्र के बेड़ो-लोहरदगा मुख्य मार्ग पर तुको गांव स्थित मस्जिद के समीप बुधवार की शाम अज्ञात चारपहिया वाहन की टक्कर से पैदल जा रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया।



जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बेड़ो थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गश्ती दल में शामिल सहायक अवर निरीक्षक अक्षय सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), बेड़ो पहुंचाया। सीएचसी में चिकित्सक डॉ. काजल ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।

घायल युवक अर्धबेहोशी की हालत में अपना नाम परदेशिया उरांव तथा घर ग्राम चरिमा बता रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार वाहन की तलाश की जा रही है।

रांची, गुरुवार
26.11.2026
वर्ष : 11, अंक : 351, पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

खबरे हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

झारखंड विधानसभा से एसआईआर पर राजकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा हुई।

चर्चा के बाद मतदाताओं की परेशानियों को लेकर सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने के लिए एक राजकीय संकल्प क पारित कर दिया गया।

विधानसभा में चर्चा के बाद स्पीकर रबिंद्रनाथ महतो ने सदन में करीब साढ़े चार घंटे तक चली बहस के बाद इस संकल्प को पारित किए जाने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाई जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रियागत दुरूहता के कारण मतदाताओं को परेशानियां हो रही है।

इन परेशानियों से सभी सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने के लिए राज्य सरकार के संकल्प पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव है।

उन्होंने इस राजकीय संकल्प पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों से सहमति-असहमति के बारे में पूछा और इसे ध्वनिमत से पारित किए जाने का ऐलान किया।

इससे पहले संसदीय कार्य और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से एसआईआर को लेकर एक राजकीय संकल्प सदन में पेश किया। उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से राज्य में जारी एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की।

किशोर ने कहा कि एसआईआर कराए जाने पर राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी भी योग्य मतदाता को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। विधानसभा में मंत्री की ओर तर्क दिया गया कि एसआईआर के वर्तमान स्वरूप में अपनाई जा रही प्रक्रियागत मुश्किलों के कारण वैध मतदाताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए सर्वमान्य एसओपी तैयार किए जाने के बाद ही नए सिरे से एसआईआर कराया जाए। उन्होंने बताया कि विभिन्न संचार माध्यमों से सरकार को जानकारी मिली है कि



झारखंड के कुल 2.64 करोड़ मतदाताओं में से पहले चरण के प्रारूप प्रकाशन में 2.21 करोड़ मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया। इस तरह से लगभग 16 प्रतिशत मददाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।

प्रारूप मदताता सूची में प्रकाशित होने के बाद 2.21 करोड़ वोटरों में से लगभग 27 प्रतिशत वोटरों को संदेहास्पद मानते हुए नोटिस जारी किया गया।

नोटिस दिए गए मामलों में 75 प्रतिशत से अधिक मामले मात्र तार्किक विसंगति से जुड़े हैं। जिसमें मुख्य रूप से माता-पिता के नाम की वर्तनी में अंतर पाया गया है।

इस तरह से झारखंड में 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 38 प्रतिशत से अधिक वोटरों का नाम या तो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया या उन्हें संदेहास्पद मानते हुए नोटिस जारी किया गया है।

संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार, एसआईआर के कारण झारखंड के मतदाताओं को दस्तावेज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने बताया कि कई वोटरों, विशेषकर बुजुर्गों के पास जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट या मांगे गए 11 दस्तावेज में कोई भी उपलब्ध नहीं है।

आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता या जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं स्वीकार करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।

आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पुरानी सूची में नाम की वर्तनी अलग-अलग होने के कारण कई आवेदन लंबित है।

झारखंड के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे महानगरों में काम करते हैं। फार्म भरने के लिए वो समय पर वापस नहीं आ सके।

घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, तो उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटने का खतरा उत्पन्न हो गया। दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को भी इसी तरह की परेशानियां हुई।

1987 से पहले जन्मे बुजुर्ग मतदाताओं से उनके माता-पिता के दस्तावेज मांगे गए, जो अधिकांश के पास उपलब्ध नहीं थे।

विवाह के बाद दूसरे गांव में रहने वाली महिलाओं का नाम कई बार मायके की मतदाता सूची में था, लेकिन ससुराल की सूची में नहीं था। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अद्यतन दस्तावेजों के अभाव में अधिक जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा।

प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय दिया गया। बीएलओ को 2-3 सप्ताह में 1000 से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना था। कई मतदाताओं की शिकायत थी कि बीएलओ एक बार उनके घर आए, जबकि उस समय वो काम या खेतों में व्यस्त थे।

फार्म हिंदी और अंग्रेजी में होने के कारण कई ग्रामीण मतदाताओं को उसे भरने में सहायता की जरूरत पड़ी। स्मार्टफोन की अनुपलब्धता और ओटीपी की समस्याओं के कारण ऑनलाइन सुधार पोर्टल का उपयोग करना कठिन रहा।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई घुसपैठिए और विदेशी नागरिकों के राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र और आधार पहचान पत्र बना लिए जाने की जानकारी मिली।

उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद इससे पहले भी कई बार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई। इसलिए इसका विरोध किया जाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर पात्र वोटरों नाम नहीं काटा चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आई है, वो सीओ-बीडीओ और अन्य अधिकारियों के टालमटोल रवैये के कारण सामने आई।

इस प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद के सुरेश पासवान, जेएलकेएम के जयराम महतो, जदयू के सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने हिस्सा लिया।

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ने कहा कि 11 अगस्त को सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

उन्होंने बताया मुख्यमंत्री की ओर से राज्यहित से जुड़े दो महत्त्वपूर्ण विषयों पर सदन में व्यापक विचार- विमर्श किये जाने के लिए दिनांक 25 और 26 नवम्बर को सभा की बैठक बुलाये जाने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने कहा कि दो दिवसीय बैठकों में जिन विषयों पर सदन विचार करने जा रहा है।उनका सीधा संबंध राज्य की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, आर्थिक हितों और राज्य के भावी विकास से है।

विधानसभा अध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर राजकीय संकल्प पारित होने के बाद आज विधानसभी की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में गुरुवार को एमडीआर बिल पर चर्चा की जायेगी।

संक्षिप्त खबरें

कांग्रेस का देशव्यापी संविधान रक्षा मार्च कल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी और मताधिकार से वंचित किए जाने के आरोप पर 26 नवंबर को संविधान दिवस पर देशभर में ह्यसंविधान रक्षा मार्चह्न की घोषणा की है। पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को बयान में कहा कि सभी प्रदेश कांग्रेस समितियां अपने-अपने राज्यों में बड़े स्तर पर मार्च आयोजित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लखनऊ में मार्च में शामिल होंगे। पार्टी ने छात्रों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और नागरिक समाज के लोगों से शामिल होने की अपील की है। वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के सामने वोट चोरी के दस्तावेजी साक्ष्य रखे हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा में फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों, आलंद में हजारों वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के सुनियोजित प्रयासों तथा हरियाणा और अन्य राज्यों में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया। ये घटनाएं मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर हेरफेर की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष जांच कराने के बजाय इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष से हलफनामा मांगा और जांच एजेंसियों की ओर से मांगी गई जानकारी भी साझा नहीं की।

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित मामलों को निरस्त करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल कई याचिकाओं के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय ज्यादा संपत्ति है। राहुल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने भी मांग की है। मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि वो राहुल गांधी की संपत्तियों का पता करे।

होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए संस्थान मिलकर करें काम : राष्ट्रपति

एजेंसी

भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से होम्योपैथी के क्षेत्र में मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने के लिए आपसी सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की भविष्य की विश्वसनीयता और अकादमिक प्रतिष्ठा काफी हद तक उसके अनुसंधान की वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और उससे प्राप्त होने वाले नैदानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय



होम्योपैथी वैज्ञानिक सम्मेलन में शिरकत करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी भारत की विविध स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुलभ, समतामूलक, वैज्ञानिक दृष्टि से जिम्मेदार और जनहित के प्रति संवेदनशील बनाने में संस्थानों, शोधकताओं, शिक्षकों तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा से जुड़ा प्रत्येक निर्णय मरीज की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का अंतिम उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसलिए चिकित्सा के प्रत्येक क्षेत्र में मरीज का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

उन्होंने होम्योपैथी के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण नैदानिक साक्ष्यों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी की विश्वसनीयता और शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान में वैज्ञानिक ईमानदारी तथा प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य है। उन्होंने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पेशेवर संगठनों से इस दिशा में मिलकर काम करने तथा अनुसंधान की मजबूत परंपरा विकसित करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

बिहार कैबिनेट की बैठक अब डिजिटल सिस्टम से

एजेंसी

पटना। बिहार में कैबिनेट की बैठकें अब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार ने ई-कैबिनेट प्रणाली को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस नई व्यवस्था के तहत कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की उपस्थिति पहले की तरह भौतिक रूप से होगी, लेकिन बैठक से संबंधित संलेख, प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज अब कागजी फाइलों के बजाय डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल कागज की खपत और सरकारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।

इस पूरी परियोजना पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके तहत मंत्रियों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से वे कैबिनेट की बैठक से संबंधित दस्तावेजों को पढ़ और देख सकेंगे। साथ ही किसी विभाग की ओर से अपलोड किए गए संलेख को संबंधित मंत्री भी आसानी से देख सकेंगे। इससे प्रस्तावों के अध्ययन और उन पर आगे की कार्रवाई करने में सहूलियत होगी।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि ई-कैबिनेट प्रणाली को भविष्य में नियमित रूप से संचालित करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की मौजूदगी फिजिकल ही रहेगी, लेकिन बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर किए गए खर्च की भरपाई छह से सात महीने में हो जाने का अनुमान है। अब तक कैबिनेट की बैठकों के लिए बड़ी संख्या में दस्तावेजों की छपाई और वितरण करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से इस पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा।

सत्ता बदलते ही बदल जाता है मुकदमा चलाने का नजरिया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

एजेंसी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आपराधिक न्याय प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका के कथित हस्तक्षेप पर गहरी चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के साथ मुकदमों को चलाने का रवैया भी अक्सर बदल जाता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी.



सेंथिल बालाजी से जुड़े 'नौकरी के बदले नकदी' (कैश-फॉर-जॉब्स) मामले की सुनवाई के दौरान की। उच्चतम न्यायालय अब 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने अभियोजन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे बुरा पहलू यह है कि राजनीतिक कार्यपालिका के बदलने के साथ ही मुकदमों को चलाने का तरीका भी बदल जाता है। एक सरकार मामले को लटकाती है तो दूसरी अचानक जल्दबाजी दिखाती है।

सुनवाई में बालाजी के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में मामला आरोप तय करने के चरण में है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आरोप भले गंभीर हों लेकिन किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस बागची ने कहा कि 2021-22 के मामलों पर 2026 में सुनवाई हो रही है, ऐसे में कुछ दिन की देरी से आसमान नहीं गिर पड़ेगा।

यह मामला 2011 से 2015 के बीच परिवहन विभाग की भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही 14 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय अब 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी।

उड़ीसा में सक्रिय रहे 13 लाख के इनामी दो नक्सली कैडरों का छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण

एजेंसी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति एवं सुरक्षाबलों द्वारा पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रभावित होकर उड़ीसा में सक्रिय 13 लाख के इनामी दो नक्सली कैडरों ने बुधवार को बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों में नागमणी कुड़मे ऊर्फ शीला पति जगदीश इरपा (उम्र 32 वर्ष) जाति मुरिया निवासी चिपुरभटटी थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर, संगठन, ओड़िशा राज्य अन्तर्गत बटालियन नम्बर 08 के सीवायपीसी, पदनाम- सीवायपीस, घोषित इनाम- 08 लाख एवं गंगा सोढ़ी ऊर्फ सोनू पिता मंगल सोढ़ी (उम्र 26 वर्ष) जाति मुरिया निवासी डोडीतुमनार गादेपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, छग संगठन, उड़ीसा राज्य अन्तर्गत कालाहांडी एरिया कमेटी सदस्य पद/रैंक- एसीएम, घोषित इनाम- 05 लाख शामिल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित नागमणी कुड़मे ऊर्फ शीला संगठन में भर्ती- वर्ष 2006झ7 में गांधी ताती उर्फ हरबू के माध्यम से पीएलतीए सदस्य के रूप में नक्सली संगठन में भर्ती हुई । वर्ष 2009 में एसीएम, वर्ष 2016 में डीव्हीसीएम तथा वर्ष 2021 में ओडिशा राज्य के कंपनी नं. 8, के-केबी(एन) क्षेत्र में सीवायपीसी पद पर कार्यरत रही।

वहीं, आत्मसमर्पित गंगा सोढ़ी ऊर्फ सोनूवर्ष 2008 में ग्राम डोडीतुमनार बाल संघम सदस्य के रूप में संगठन में शामिल हुआ। वर्ष 2010 में भूमकाल मिलिशिया सदस्य रहा तथा जनवरी 2012 में गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत पीएलजीए सदस्य के रूप में कार्य किया । दिसंबर 2012 में नेशनल पार्क एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 02 में भेजा गया। वर्ष 2019 में पीपीसीएम पद पर जवाबदारी दी गई । दिसंबर 2020 से मार्च 2026 तक ओड़िशा राज्य अंतर्गत कालाहांडी एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) के पद पर कार्यरत रहा।

उक्त दोनों आत्मसमर्पित नक्सली संगठन में रहते हुए छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रही तथा कई नक्सली वरदातों एवं मुठभेड़ों में शामिल रही।

कैबिनेटः डाक संचालन और संपदा प्रबंधन योजनाओं के विस्तार को मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डाक सेवा के संचालन और ढांचागत सुविधाओं के रखरखाव के लिए दो अलग-अलग फैसलों में 1,141 और 1,491 करोड़ की दो योजनाओं के अगले 5 सालों के संचालन को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डाक विभाग की योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

वैष्णव ने बताया कि डाक संचालन योजना को 16वें वित्त आयोग की पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं को अपग्रेड करना, मेल और पार्सल सेवाओं को संचालित करना, ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय डाक लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना और डिलीवरी सुविधाओं के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनकी सुविधाओं में वृद्धि करना है।

वहीं संपदा प्रबंधन योजना के तहत 190 नई विभागीय पोस्ट बिल्डिंग बनेगी, 5,050 पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड किया जाएगा, 200 ऐतिहासिक डाक बिल्डिंग को संरक्षित किया जाएगा, 150 डाक सेवा से जुड़ी रिहायशी कॉलोनी को रिनोवेट किया जाएगा और बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा।

निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना लाई सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य सीआईई और इसके पुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। योजना की अवधि 8 वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक) होगी। योजना के दो घटक हैं, पहला बिक्री-आधारित प्रोत्साहन और सीआईई परीक्षण सुविधा। ब्रिक्री आधारित प्रोत्साहन के तहत पात्र ओईएम और पुर्जा निमार्ताओं के लिए पांच वर्षों में होने वाली अतिरिक्त बिक्री पर 13 से 8 प्रतिशत तक का श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं परीक्षण सुविधा के तहत एक समर्पित परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए 375 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सीआईई इकोसिस्टम के निर्माण से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। सप्लाई चेन की सुरक्षा बेहतर होगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी।

असम के सिलचर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार असम के सिलचर जिले के डोलू में 2,014 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास करेगी। एयरपोर्ट से पूर्वोत्तर भारत की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास गलियारों (ग्रोथ कॉरिडोर) के साथ कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे के तौर पर 12,351 वर्ग मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। व्यस्ततम समय में एयरपोर्ट की क्षमता 800 यात्रियों की होगी। इसमें 2,705 मीटर ७ 45 मीटर का रनवे होगा। साथ ही छह एयरबस ए-320 विमानों के लिए एप्रन पार्किंग क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट दक्षिण असम और बराक घाटी के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा। इससे मौजूदा सिलचर एयरपोर्ट की परिचालन और जगह संबंधी कमियों दूर होंगी। इससे दक्षिण असम और पड़ोसी राज्यों के नजदीकी इलाकों में हवाई यातायात की बढ़ती मांग पूरी होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

सीईआईआर पोर्टल की मदद से बोकारो पुलिस ने बरामद किए 73 गुम मोबाइल, मालिकों को लौटाए

जनवरी से अब तक 757 मोबाइल बरामद कर वास्तविक धारकों को सौंपे, मोबाइल चोरी के तीन मामले भी दर्ज

बिभा संवाददाता



बोकारो। बोकारो पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से पिछले एक महीने में 73 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बुधवार, 25 नवंबर को सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। वहीं, जनवरी 2026 से अब तक जिले में कुल 757 मोबाइल बरामद कर धारकों को लौटाए जा चुके हैं।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए सीईआईआर पोर्टल का प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत 25 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक चास, बेरमो (तेनुघाट), नगर, मुख्यालय और बोकारो क्षेत्र में अभियान चलाकर 73 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामदगी के बाद संबंधित थाना एवं ओपी की ओर से मोबाइल धारकों को सूचना दी गई और आवश्यक सत्यापन के बाद उनके मोबाइल सौंप दिए गए।

पुलिस के अनुसार, जनवरी से अब तक चलाए गए अभियान में कुल 757 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल चोरी से संबंधित तीन मामले दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है।

मोबाइल गुम होने पर सीईआईआर पोर्टल पर करें शिकायत

बोकारो पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर तत्काल नजदीकी थाना में इसकी सूचना दें। साथ ही भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर जाकर मोबाइल से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज कराएं। पोर्टल के माध्यम से गुम या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने और उसके इस्तेमाल पर नजर रखने में मदद मिलती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो इसकी जानकारी संबंधित थाना और आवेदक तक पहुंच सकती है।

पुलिस ने लोगों से मोबाइल की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और मोबाइल गुम या चोरी होने की स्थिति में बिना देर किए इसकी सूचना देने की अपील की है।

सेक्टर-12 के आवास में बड़ी चोरी, 17 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर





शादी समारोह में राजगंज गया था पूरा परिवार, घर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

बिभा संवाददाता

बोकारो। बोकारो के सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सेक्टर-12सी स्थित आवास संख्या 3073 में चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी काटकर करीब 17 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन और 10 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। वारदात के समय घर के सभी सदस्य धनबाद जिले के राजगंज में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

जानकारी के अनुसार, आवास में राजेंद्र दास अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के सीसीएस विभाग में कार्यरत हैं। परिवार के सभी सदस्य शादी समारोह में शामिल होने राजगंज गए हुए थे। इसी दौरान घर को खाली पाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी काटी और अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से करीब 15 लाख रुपये के सोने के आभूषण, जिनमें कंगन, अंगूठी, मांगटीका सहित कई कीमती गहने शामिल हैं, तथा लगभग तीन लाख रुपये के चांदी के जेवरात और बर्तन लेकर फरार हो गए। इसके अलावा घर में रखे 10 हजार रुपये नकद भी चोरी कर लिए।

गृहस्वामिनी आरती कुमारी ने बताया कि वह अपनी मौसी के बेटे की शादी में शामिल होने परिवार के साथ राजगंज गई थीं। वापस लौटने पर घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर प्रवेश करने पर कमरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे जेवरात व नकदी गायब थे। इसके बाद उन्होंने तत्काल सेक्टर-12 थाना पुलिस को घटना की सूचना दी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा चोरी की घटना से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है। समाचार लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस ने गृहस्वामी को आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने बुलाया है।

संक्षिप्त खबरें

कसमार में बाल विवाह मुक्त जागरूकता का आयोजन बच्चों ने लिया संकल्प



कसमार (बिभा): कसमार प्रखंड के बरईकला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय करकटाकला में सहयोगिनी संस्था की ओर से बाल विवाह एवं बाल श्रम मुक्त जागरूकता अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर चर्चा करते हुए अपने गांव को बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापक श्वेता प्रजापति ने बताया कि बच्चों को किताबों की जरूरत है, जिम्मेदारियों की नहीं। बाल विवाह एक बच्चे का बचपन, पढ़ाई और पूरा भविष्य छीन लेता है। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सब शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम बच्चों को जागरूक करें और माता-पिता को भी समझाएं कि कम उम्र में शादी करना अपराध है। बताया गया कि अगर गांव में कहीं भी बाल विवाह या बाल श्रम की जानकारी मिलती है, तो विद्यालय एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को देने का काम करे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और सहयोगिनी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों ने अपने गाँव को बाल विवाह और बाल श्रम से मुक्त बनाने का संकल्प लिया। मौके पर स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

ट्रैक्टर पर गिरा बिजली का तार, चालक बाल-बाल बचा



कसमार (बोकारो)(बिभा) . कसमार प्रखंड के दांतू गांव स्थित ऊपर कुल्ही में गुरुवार को बिजली का तार टूटकर एक ट्रैक्टर पर गिर गया. गनीमत रही कि इस घटना में ट्रैक्टर चालक बाल-बाल बच गया. तार में बिजली प्रवाहित होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था. दांतू पंचायत के मुखिया चंद्रशेखर नायक ने बताया कि गांव में बिजली के तार और खंभे काफी जर्जर हो चुके हैं. आये दिन तार टूटकर गिरने की घटनाएं हो रही हैं. इससे ग्रामीणों के बीच हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. गुरुवार की घटना में ट्रैक्टर चालक की जान बच गयी, लेकिन स्थिति गंभीर हादसे का कारण बन सकती थी. मुखिया ने बिजली विभाग से गांव में लगे सभी जर्जर तारों और खंभों को जल्द बदलने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समय रहते जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

चास मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुम हुए 3 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे



चास (बोकारो)(बिभा) : बोकारो जिला के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चास मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रकाश मंडल ने बुधवार को गुम हुए 3 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। मोबाइल मिलने के बाद मालिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।पहला मामला सागर कुमार महतो, पिता तुलसी महतो, सा० अंधरतेलिया, थाना- चास (मु०), जिला- बोकारो का है। इनका मोबाइल हरिडीह से अंधरतेलिया जाने के क्रम में गुम हो गया था। इस संबंध में सनहा संख्या- 22/26, दिनांक- 09/09/26 दर्ज कराया गया था।दूसरा मामला अमुन अंसारी, पिता स्व० उस्मान अंसारी, सा० डाबरनहाल, थाना- चास (मु०), जिला- बोकारो का है। इनका मोबाइल घर में शादी समारोह के दौरान गुम हो गया था। इस संबंध में सनहा संख्या- 18/26, दिनांक- 16/06/26 दर्ज कराया गया था।तीसरा मामला त्रिवेणी कुमार शर्मा, पिता जलेश्वर शर्मा, सा० मुर्तिरोड, थाना- चास (मु०), जिला- बोकारो का है। इनका मोबाइल मालती लाजरो अपार्टमेंट गेट के पास गुम हो गया था। इस संबंध में सनहा संख्या- 12/26, दिनांक- 01/08/26 दर्ज कराया गया था।तीनों मामलों में चास मुफस्सिल थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। बरामद मोबाइलों को सत्यापन के बाद संबंधित मालिकों को सौंप दिया गया।मोबाइल वापस पाकर तीनों मालिकों ने चास मुफस्सिल थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाना में सनहा दर्ज कराएं, ताकि समय पर बरामदगी की कार्रवाई की जा सके।

बीएसएल में निजी सुरक्षा गार्डों की बहाली के विरोध में उतरे होमगार्ड जवान, डीसी को सौंपा ज्ञापन

पहले से तैनात जवानों को हटाने की कथित तैयारी पर जताई नाराजगी, निजी सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने की मांग

बिभा संवाददाता



बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में निजी सुरक्षा गार्डों की बहाली और पहले से तैनात होमगार्ड जवानों को हटाने की कथित तैयारी के विरोध में जवानों का आक्रोश सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों ने बोकारो उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। साथ ही उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर निजी सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने और वर्षों से कार्यरत होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से नहीं हटाने की मांग की।

इस दौरान होमगार्ड जवान रुपांजलि ने बताया कि वे लंबे समय से बीएसएल में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं। धरना-प्रदर्शन और विषम परिस्थितियों में भी जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाई है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि कर्तव्य पालन के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। इसके बावजूद कृत्रिम पैर के सहारे वह आज भी बीएसएल में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं।

वहीं, महिला होमगार्ड जवान गायत्री देवी ने बताया कि वह वर्ष 1990-91 से बीएसएल में तैनात हैं। वर्ष 1996-97 के आंदोलनों के दौरान भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में टेंट लगाकर ड्यूटी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएल में 600 होमगार्ड जवानों के नाम पर करीब 400 जवानों से ही काम लिया जा रहा है, जबकि शेष 200 जवानों का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है।

एक अन्य होमगार्ड जवान ने कहा कि वर्ष 1984 से गृह रक्षक बीएसएल की सुरक्षा व्यवस्था संभालते आ रहे हैं। वर्ष 2010 में भी उन्हें हटाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नए अधिकारी निजी एजेंसियों को बढ़ावा देकर निजी सुरक्षा कर्मियों की बहाली करना चाहते हैं। इससे वर्षों से सेवा दे रहे होमगार्ड जवानों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।

होमगार्ड जवानों ने प्रबंधन से मांग की कि उनके लंबे सेवा अनुभव और योगदान को देखते हुए उन्हें कार्य से हटाने का निर्णय वापस लिया जाए। साथ ही उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप कर जवानों के हितों की रक्षा करने की अपील की।

अगले माह हैप्पी स्ट्रीट का पांचवां संस्करण, सड़क पर जुटेगा फिटनेस और संस्कृति का संगम



बोकारो(बिभा): शहरवासियों को एक बार फिर सर्दियों की सुबह सड़क पर योग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन के एक्टिव बोकारो-हेल्दी बोकारो अभियान के तहत हैप्पी स्ट्रीट के पांचवें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी शुरूआत दिसंबर के तीसरे सप्ताह से होने की संभावना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, सेक्टर-4 स्थित गांधी चौक से सेक्टर-3 के बोकारो मॉल मोड़ तक सड़क की एक लेन पर हैप्पी स्ट्रीट आयोजित होगी। तय रविवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यह मार्ग नो-व्हीकल जोन रहेगा, जहां बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सुरक्षित माहौल में फिटनेस और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस कार्यक्रम का यह पांचवां संस्करण है, जिसके लिए बीएसएल ने विशेष कमेटी गठित की है। ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी का दर्जा मिलने के बाद शहर में जनभागीदारी और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे आयोजनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

भावपूर्ण समदाओन गीतों के बीच सामा-चकेवा की विदाई, बहनों ने जलाया चुगला का मुंह

बिभा संवाददाता



बोकारो। मिथिलांचल की समृद्ध लोक संस्कृति और भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा-चकेवा पर्व मंगलवार की रात बोकारो में पारंपरिक उल्लास और भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मिथिला सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में सेक्टर-4ई स्थित मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल परिसर में सामा-चकेवा की विदाई का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मैथिल परंपरा के अनुसार महिलाओं ने पारंपरिक समदाओन गीत गाकर सामा-चकेवा को भावभीनी विदाई दी और भाइयों की दीघार्यु एवं सुख-समृद्धि की कामना की। चास-बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने मिट्टी से निर्मित सामा-चकेवा, सतभइया, वृंदावन, चुगला, ढोलिया-बजनिया, बन तितिर और पंडित सहित विभिन्न पारंपरिक आकृतियों की पूजा-अर्चना कर पर्व की रस्में पूरी कीं। इसके बाद परंपरा के अनुसार सन (पटुआ) से बने चुगला का मुंह जलाकर झुलसाया गया। अंत में सभी मूर्तियों का सामूहिक रूप से विसर्जन किया गया।

इस अवसर पर परिषद के महासचिव नीरज चौधरी ने कहा कि सामा-चकेवा मिथिला की महान लोक संस्कृति से जुड़ा भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व है। इस पर्व की परंपरा और महत्ता का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मिथिला के पारंपरिक पर्व-त्योहारों, कला और संस्कृति से जोड़कर रखना परिषद का प्रमुख उद्देश्य है।

कार्यक्रम के दौरान मिथिला महिला समिति की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों की मनमोहक प्रस्तुति से माहौल को भावविभोर कर दिया।

इस अवसर पर मिथिला महिला समिति की ओर से दर्जनों जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण भी किया गया। आयोजन में परिषद के निदेशक मंडल के सदस्य कृष्ण चंद्र झा एवं विजय कुमार झा, वित्त सचिव मिहिर मोहन ठाकुर, सांस्कृतिक कार्यक्रम निदेशक अरुण पाठक के अलावा बटोही कुमर, अविनाश कुमार झा अवि, गोविंद कुमार झा, अरविंद मिश्रा, गिरिजानंद मिश्र, पशुपति झा, शंभु झा और रौशन कुमार तरुण उपस्थित थे।

इंटर-स्कूल संविधान क्विज में एमजीएम स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन

बिभा संवाददाता



बोकारो। इंटर-स्कूल संविधान क्विज प्रतियोगिता 2026 में एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, बोकारो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 11 विद्यालयों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल ने चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

प्रतियोगिता का आयोजन 23 नवंबर को चिन्मय विद्यालय, बोकारो के सभागार में डॉ. राधाकृष्णन सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स, बोकारो के तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति समझ विकसित करने, नागरिक जागरूकता बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना था।

एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कक्षा नौवीं के आदित्य बर्मन राय और कक्षा ग्यारहवीं की उन्नति गुप्ता ने प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों विद्यार्थियों ने अपने संवैधानिक ज्ञान, आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी प्रतिभागी विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय को प्रथम स्थान के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

इस सफलता में मार्गदर्शक शिक्षिकाओं बिंसी मधुर, विवेक कुमार तिवारी और कंचन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन से विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की बेहतर तैयारी करने में मदद मिली।

विद्यालय के प्राचार्य फादर डॉ. जोशी वर्गीस ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी मेहनत, लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने मार्गदर्शक शिक्षकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की और विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी उत्साह एवं समर्पण के साथ सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ईएसएल स्टील के मेगा स्वास्थ्य शिविर में 236 ग्रामीणों की हुई स्वास्थ्य जांच

बिभा संवाददाता



बोकारो। ईएसएल स्टील लिमिटेड की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को मधुनिया में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कंपनी के सीएसआर विभाग ने अपनी प्रमुख स्वास्थ्य पहल ह्यप्रोजेक्ट आरोग्यह्ल के तहत सिटिजन्स फाउंडेशन के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। इसमें कुल 236 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाया।

शिविर का उद्घाटन वार्ड सदस्य जब्बार अंसारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं ईएसएल स्टील लिमिटेड की सीएसआर टीम की उपस्थिति में किया गया। शिविर में जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और त्वचा रोग विशेषज्ञ ने मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। वहीं, ममता मूर्ति आई हॉस्पिटल की टीम ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने और आभा (अइलअ) कार्ड के पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

शिविर में सामान्य चिकित्सा परामर्श के लिए 77, बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श के लिए 59, हड्डी रोग संबंधी जांच के लिए 39 और त्वचा रोग संबंधी परामर्श के लिए 32 मरीज पहुंचे। इसके अलावा 29 लोगों की आंखों की जांच की गई। वहीं, 18 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने तथा 61 लोगों का आभा कार्ड पंजीकरण कराने में सहायता की गई।

निवारक स्वास्थ्य जांच के तहत 45 लोगों की ब्लड शुगर, 54 लोगों का ब्लड प्रेशर और 10 लोगों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। इस दौरान ग्रामीणों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और बीमारियों के शुरूआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने के प्रति जागरूक भी किया गया।

इस अवसर पर ईएसएल स्टील लिमिटेड के सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक रवीश शर्मा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का आधार है। प्रोजेक्ट आरोग्य के माध्यम से कंपनी ग्रामीण एवं जरूरतमंद समुदायों तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और निवारक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिविर में 236 लोगों की भागीदारी इस तरह की पहल की उपयोगिता को दशार्ती है। कंपनी भविष्य में भी सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ऐसे प्रयास जारी रखेगी।

ईएसएल स्टील लिमिटेड की ओर से प्रोजेक्ट आरोग्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित जांच और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कंपनी की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूत करना है।

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर टीम एहसास फाउंडेशन ने लगाया सेवा शिविर, नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं पर की पुष्पवर्षा



बिभा संवाददाता

चास (बोकारो)। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर टीम एहसास फाउंडेशन की ओर से चास में सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं एवं संगत का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर प्रेम और सम्मान प्रकट किया गया। साथ ही पानी, बिस्किट, केक, जूस और चॉकलेट वितरित कर सेवा भाव के साथ संगत की सेवा की गई।

इस आयोजन के माध्यम से फाउंडेशन के सदस्यों ने गुरु नानक देव जी के प्रेम, भाईचारे, समानता और मानव सेवा के संदेश को आत्मसात करते हुए अपनी सहभागिता निभाई।

इस अवसर पर मोहम्मद साहिल शेख ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें आपसी प्रेम, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देती हैं। उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए समाज में आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करना ही हमारी सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि इंसानियत और मानवता का कोई धर्म नहीं होता। टीम एहसास फाउंडेशन हमेशा समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा जरूरतमंदों की सेवा के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीम एहसास फाउंडेशन के सभी सदस्यों एवं सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा।

एसआईआर के जरिए बंगाल की तरह झारखंड में सत्ता पाना चाहती है भाजपा : प्रदीप यादव

बिभा संवाददाता

रांची। एसआईआर और एमएमडीआर संशोधन बिल पर विशेष चर्चा के दौरान झारखंड विधासनसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी सत्ता पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देखा कि झारखंड में उनकी दाल नहीं गल रही है तो एसआईआर के जरिए वोट में गडबडी का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर से जुडी परेशानी भाजपाजनित है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को आम जनता से जुडी परेशानियों पर बोलना चाहिए,



न कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि की तरह व्यतवहार करना चाहिए। प्रदीप यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 38 लाख लोगों के नाम मातदाता सूची से हटा दिए गए। इसमें से 93 प्रतिशत (35 लाख) मतदाता वैध हैं। उन्होंखने चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म छह में किए गए बदलाव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आज नहीं कल जेल जाना ही होगा।

प्रदीप यादव ने कहा कि देश का सौभाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में गई, जहां पंडित नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, जबकि सरदार पटेल और बाबा साहब जैसे राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर देश का संविधान की आलोचना करने का भी आरोप लगाया।

साथ ही उन्होंने झारखंड के मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार पर भी पाकुड और महागामा के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर तंज कशा।

एसआईआर में फर्जी नामों का ब्योरा सार्वजनिक करे सरकार : जयराम

रांची। जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सदन में एसआईआर को लेकर सरकार की ओर से लाए गए संकल्प पर चर्चा में कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में छोटी-मोटी त्रुटियां होना आम बात है। इन त्रुटियों के आधार पर मतदाताओं को परेशान करने के बजाय सरकार को एसआईआर में छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधारने के साथ-साथ फर्जी बताकर मतदाता सूची से हटाए गए नामों का ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। इससे स्थिति और स्पष्ट होगी। बुधवार को विशेष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही की दूसरी पाली में जयराम महतो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डेटा और तकनीक का युग है। ऐसे में दस्तावेजों में नाम, पता या अन्य जानकारियों में मामूली अंतर होना स्वाभाविक है। इन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास होना चाहिए, न कि उन्हें आधार बनाकर मतदाताओं को संदेह के घेरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का समाधान सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा। सरकार को निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यावहारिक पहल करनी चाहिए, ताकि दस्तावेजों में मौजूद छोटी-मोटी गलतियों को ठीक कराया जा सके और किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से विशेष रूप से मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम फर्जी बताकर सूची से हटाए गए हैं, उनका पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखा जाए। सरकार सार्वजनिक करे कि कितने नाम हटाए गए, किन आधारों पर उन्हें फर्जी माना गया और इसके पीछे क्या कारण थे।
जयराम महतो ने कहा कि तकनीक के इस दौर में हटाए गए नामों और उनके कारणों की जानकारी जुटाना मुश्किल नहीं है। इसलिए सरकार को आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर आंकड़ों के साथ सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

एनयूएसआरएल ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक को दी विदाई, कहा– न्यायिक निर्णयों का आलोचनात्मक विश्लेषण जरूरी



बिभा संवाददाता

रांचीः नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार ने उनके मार्गदर्शन, सहयोग और जुड़ाव के प्रति आभार जताया।

समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सोनक ने विधि शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षकों, शोधार्थियों व विधि विशेषज्ञों से न्यायिक निर्णयों के केवल अध्ययन तक सीमित न रहने, बल्कि उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निर्णयों की तुलना अन्य मामलों, विधिक सिद्धांतों व विचारधाराओं से करते हुए शोध पत्र, टिप्पणियां व लेख लिखना विधिक जगत के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा।

विधि शिक्षकों की भूमिका पर बात करते हुए न्यायमूर्ति सोनक ने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य के विधि विशेषज्ञों और न्यायपालिका के कर्णधारों को तैयार करने वाली नर्सरी हैं। यहां विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, स्वतंत्र चिंतन और स्वयं विचार करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने दार्शनिक वोल्तेयर का उल्लेख करते हुए कहा कि विचारों से असहमति के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।

अपने जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रति उनका स्नेह और संबंध सदैव बना रहेगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान की सहायता करना उनके लिए कृपा नहीं, बल्कि अधिकारपूर्वक किया जाने वाला दायित्व होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय को अपनी उपलब्धियों व चुनौतियों का संतुलित आकलन करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी दिया।

कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल ने मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संबंध औपचारिक पद और कार्यकाल से आगे तक बने रहेंगे। कार्यक्रम में कुलसचिव प्रो. (डॉ.) धर्मेंदर कुमार सहित अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद रहे। समारोह के अंत में एनयूएसआरएल परिवार ने न्यायमूर्ति सोनक के स्वस्थ, सुखमय व उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संक्षिप्त खबरें

बिहार एमएलसी सुनील चौधरी की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम हेमन्त सोरेन



रांची(बिभा): मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उनकी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को डोरंडा के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा स्थित बिहार विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) सुनील चौधरी के आवास पहुंचे। यहां वे सुनील चौधरी की सुपुत्री सुरभि श्री के वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। इस मांगलिक अवसर पर मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने नवदंपती को स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना की। दोनों ने सुनील चौधरी तथा उनके परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर अपनी मंगलकामनाएं व्यक्त कीं और पारिवारिक खुशी में शामिल होकर प्रसन्नता जाहिर की।

भुवनेश्वर के सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ सरला बिरला विवि का करार



रांची(बिभा): बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में एकेडमिक लीडरशिप विषय पर आयोजित व्याख्यान में सरला बिरला विश्वविद्यालय (एसबीयू), रांची के महानिदेशक प्रो. गोपाल पाठक ने वर्तमान दौर में इसकी भूमिका, चुनौतियों और खूबियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उच्च शिक्षा में एकेडमिक लीडरशिप की आवश्यकता तथा संवाद (कम्युनिकेशन) में इसकी अहम भूमिका पर अपने विचार रखते हुए विद्यार्थियों के लिए नेतृत्वकताओं को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने और स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। भुवनेश्वर प्रवास के दौरान प्रो. गोपाल पाठक ने सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहां के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर चर्चा की। दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए करार के तहत अब एसबीयू के विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए सेंचुरियन विश्वविद्यालय जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कीट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सरनजीत सिंह और प्रो. गोपाल पाठक के बीच दोनों संस्थानों के मध्य एमओयू करने पर भी सहमति बनी। विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ हुए इन समझौतों पर सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान, कुलपति प्रो. सी. जगनाथन तथा राज्यसभा सांसद सह निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने हर्ष व्यक्त किया है।

एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने ग्रेटर रांची में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, 149 श्रमिक लाभान्वित



रांची(बिभा): एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) ने 24 नवंबर को ग्रेटर रांची स्थित एनएमएल कार्यालय भवन परिसर के निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। एनटीपीसी की स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति आह्वान के तहत आयोजित इस शिविर में कुल 149 श्रमिकों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक सामान्य दवाइयां प्रदान की गईं। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए व्यस्तता और अन्य कारणों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराना अक्सर कठिन होता है। इस पहल के माध्यम से उन्हें कार्यस्थल पर ही सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। कंपनी प्रबंधन के अनुसार, एनएमएल अपनी सभी परियोजनाओं और कार्यस्थलों पर श्रमिकों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और आगामी महीनों में भी इस तरह के और शिविर आयोजित किए जाएंगे।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी के लिए सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें: के. रवि

बिभा संवाददाता

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड श्री के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी पूरी करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर मामले लंबित नहीं रहने दें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।



समीक्षा के दौरान उन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मामलों का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है, उनका व्यक्तिगत नियमानुसार गहन निरीक्षण किया जाए। आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति एवं तथ्यों का सत्यापन करते हुए संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए तथा प्रत्येक मामले में नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाए।

के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में मतदाताओं के सुनवाई एवं सत्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्य मतदान केंद्रों का नजरी नक्शा, मतदान केंद्र की फोटो, जियो टैगिंग आदि कार्य का भी अपडेशन का कार्य पूरा करें। इसके साथ-साथ ड्राफ्ट रोल के उपरांत प्रत्येक दिन प्राप्त हो रहे आवेदनों का उसी दिन ईसीआईनेट पर अपडेशन सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केंद्र क्षेत्रों में अभी भी नए मतदाता के नामांकन हेतु कम आवेदन प्राप्त हो रहें हैं वहां सुपरचेकिंग के दौरान पदाधिकारी होम टू रोल वेरीफिकेशन का कार्य की गहन समीक्षा करें एवं भौतिक समीक्षा के क्रम में पदाधिकारी कमसे कम लगातार 5 घरों में अवश्य जाएं एवं वहां के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल हुआ है अथवा नहीं इसकी जांच करें।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम हेमन्त सोरेन



रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उनकी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को मेन रोड स्थित होटल लेमन ट्री पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता की सुपुत्री मुस्कान प्रिया के वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। इस मांगलिक अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने नवदंपती को स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना की। दोनों ने आयुक्त विजय कुमार गुप्ता तथा उनके परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर अपनी मंगलकामनाएं व्यक्त कीं और पारिवारिक उत्सव में शामिल होकर हर्ष जताया।

सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय आईडीएसपी-वीपीडी सर्विलांस ट्रांजिशन कार्यशाला शुरू



बिभा संवाददाता

रांची। सदर अस्पताल के सभागार में बुधवार को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आईडीएसपी-वीपीडी सर्विलांस ट्रांजिशन कार्यशाला के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ।

25 से 27 नवंबर 2026 तक चलने वाली इस कार्यशाला में आठ जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारी एवं कर्मी भाग ले रहे हैं। इससे पहले राज्य के 16 जिलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि सर्विलांस और टीकाकरण एक-दूसरे से जुड़े हैं। प्रत्येक बच्चे को निर्धारित समय पर सभी टीके मिलना सुनिश्चित करना होगा। यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण का डेटा समय पर दर्ज करने पर भी उन्होंने जोर दिया।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण से रोगों की समयबद्ध रिपोर्टिंग और संभावित प्रकोपों की शीघ्र पहचान में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण में पोलियो, खसरा, रूबेला, डिप्थीरिया, काली खांसी और नवजात टिटनेस की निगरानी के साथ सैंपल संग्रह, डेटा प्रविष्टि और आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि पूर्व में यह निगरानी एवं जांच का कार्य डब्ल्यूएचओ करता था, जिसे अब एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाएगा।

कार्यक्रम में रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा और लातेहार के स्वास्थ्य पदाधिकारी इसमें शामिल हुए।

आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को लोक भवन में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने तथा सदैव जनसेवा के प्रति तत्पर और समर्पित रहने का संदेश दिया।

सड़सी - कुटासी ठन ठन पुस्तक के जरिए छोटनी कुमारी ने महाविद्यालय को गौरवान्वित किया: डॉ. दीपिका टोप्पो



रांची: डोरंडा महाविद्यालय, रांची के नागपुरी विभाग की स्नातक सेमेस्टर-2 की छात्रा छोटनी कुमारी ने जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपनी रचित पुस्तक सड़सी - कुटासी ठन ठन के माध्यम से जनजातीय समाज और संस्कृति से जुड़े अनुभवों को समाज के बीच साझा किया है। बुधवार को छोटनी कुमारी ने यह पुस्तक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दीपिका टोप्पो को समर्पित की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. दीपिका टोप्पो ने कहा कि छोटनी कुमारी जयपाल जूलियूस - हन्ना साहित्य अवार्ड पाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की रचनाकार हैं और उनकी इस उपलब्धि पर पूरा महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। उन्होंने बताया कि छोटनी असुर जनजाति से आती हैं और अपनी कविताओं व साहित्य के माध्यम से समाज के बीच जागरूकता ला रही हैं। उनकी कविता हंस पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है।

इस मौके पर महाविद्यालय के डॉ. ब्रजेश कुमार, डॉ. शिल्पी सिंह, डॉ. युगेश महतो, डॉ. कंचन मुंडा, डॉ. आलम आरा, डॉ. मार्शल पूर्ति, डॉ. अरविंद कुमार और मुन्धा कुमारी सहित अन्य प्राध्यापकों ने छोटनी कुमारी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

विधानसभा के समक्ष वैश्य मोर्चा का धरना-प्रदर्शन, 27प्रतिशत आरक्षण और वैश्य आयोग गठन की मांग

बिभा संवाददाता

रांचीः झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले बुधवार को विधानसभा के समक्ष (कुट्टे मैदान में) सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांग-पत्र (स्मार-पत्र) सौंपा गया, जिसकी एक प्रति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी भेजी गई। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने किया।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए स्मार-पत्र



में कहा गया कि मोर्चा बीते 20 वर्षों से झारखंड में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, वैश्य आयोग के गठन, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने और वैश्य समाज के खिलाफ हो रहे शोषण, दमन, हत्या व लूट की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोर्चा ने राज्य की 52 प्रतिशत आबादी से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की।

धरना-प्रदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, लक्ष्मण साहु, मुख्य प्रवक्ता रोहित कुमार साहु, संगठन सचिव दिवाकर साहु, रांची जिलाध्यक्ष कृष्णदेव साहु, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार साहु, आलोक कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य मुकेशलाल सिंदूरिया तथा युवा मोर्चा के हलधर साहु, आदित्य पोद्दार, भरत केशरी, ओम प्रकाश साव, मुकेश साहु व पिंटू साहु सहित कई पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने साझा की उपलब्धियां: प्रतिदिन 93.15 लाख लीटर दूध उत्पादन, गिरिडीह व सरायकेला में लगेंगे नए संयंत्र

बिभा संवाददाता

रांचीः राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और पशुपालन क्षेत्र की उपलब्धियों व भावी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 93.15 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 34 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जो 2024-25 में 31.99 लाख मीट्रिक टन था। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए दूध आपूर्ति पर ?5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे अधिक किसान झारखंड मिल्क फेडरेशन (जेएमएफ) की सहकारी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं।

संग्रहण में बढ़ोतरी, 2028-29 तक 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन का लक्ष्य

जेएमएफ के माध्यम से प्रतिदिन औसत दूध संग्रहण 2025-26 के 2.39 लाख किलोग्राम से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक 2.88 लाख किलोग्राम हो गया है। वर्तमान में 60 हजार से अधिक किसान जेएमएफ से जुड़े हैं, 1,085 मिल्क पूलिंग पॉइंट सक्रिय हैं, 3,490 गांव संग्रहण व्यवस्था से जुड़े हैं और 230 पंजीकृत क्रियाशील जिला सहकारी दुग्ध समितियां कार्यरत हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2028-29 तक प्रतिदिन 5 लाख किलोग्राम दूध संग्रहण का लक्ष्य रखा है।

नए डेयरी और पशु आहार संयंत्र, 100% वित्तीय सहायता

वर्तमान में जेएमएफ के 6 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की कुल क्षमता 2.80 लाख लीटर प्रतिदिन है। भविष्य के लक्ष्य के मद्देनजर गिरिडीह और सरायकेला-खरसावां में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी संयंत्र तथा रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र व दुग्ध उत्पाद डेयरी निमार्णाधीन हैं। इसके अलावा होटवार (रांची) में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पशु आहार संयंत्र के साथ गोड्डा में भी 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के नए पशु आहार संयंत्र को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है।

पशुधन विकास और ग्रामीण समृद्धि पर जोर

20वीं पशुधन गणना के अनुसार राज्य में 112.23 लाख गाय और 13.50 लाख भैंस (कुल 125.73 लाख गोवंशीय पशुधन) हैं, जिनमें 2.84 लाख क्रॉस ब्रीड गाय, 30.53 लाख देशी गाय और 4.33 लाख भैंस प्रजनन योग्य हैं। नस्ल सुधार के लिए 2021-22 से 2025-26 के बीच 61.37 लाख कृत्रिम गभार्धान किए गए हैं। मंत्री ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पशुपालकों, महिला किसानों, सहकारी समितियों व कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए आगामी वर्षों में नई उपलब्धियों का विश्वास जताया।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. : ईएल-66-26, दिनांक 23.11.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा ख्यातिप्राप्त निविदाकारों जिनके पास वैध विद्युत ठेकेदार का लाइसेंस है एवं निम्नलिखित कार्य को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम हैं, से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम एवं इसका स्थान:** आसनसोल मंडल: यूडीएल-एसटीएन, डीजीएचआर-डीयूम्सके और एमएचयूआर-एचएसडीए अनुभागों में 10000 से अधिक टीबीयू वाले एलसी गेटों की इंटरलॉकिंग के लिए गेट बिल्डिंग, रिले हट का प्रावधान। **निविदा मूल्य :** रु. 41,70,013.92, **बयाना राशि :** रु. 83,400/-, **निविदा कागजात का मूल्य :** शून्य। **कार्य के लिए समापन अवधि :** 12 माह। **बंद होने एवं खुलने की तिथि और समय :** दिनांक 15.12.2026 को 11.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट: www.ireps.gov.in में देखा जा सकता है। ASN-329/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

हमारी लोकतांत्रिक आत्मा का जीवंत घोषणापत्र है संविधान



योगेश कुमार गोयल

यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना तथा डा. भीमराव अम्बेडकर के अमूल्य योगदान और उनके विचारों, आदर्शों का स्मरण करना है।

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जो वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था लेकिन इसे 26 नवम्बर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवम्बर का दिन ही 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता के रूप में डा. भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है, जिन्होंने दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और साथ ही हमारे कर्त्तव्यों को भी निर्धारित करता है। संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा समय लगा था। वर्ष 2015 में पहली बार निर्णय लिया गया कि संविधान सभा की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया जाए और तभी से यह दिवस मनाए जाने की परम्परा शुरू हुई। यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना तथा डा. भीमराव अम्बेडकर के अमूल्य योगदान और उनके विचारों, आदर्शों का स्मरण करना है।

भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष के तौर पर डा. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति की गई। पं. जवाहरलाल नेहरू, डा राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेन्द्र प्रसाद थे और नियमानुसार संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर भी उन्हीं के होने चाहिएं थे किन्तु पं. नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। संविधान का मसौदा तैयार करने में किसी भी प्रकार की टाइपिंग अथवा प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। संविधान लागू होने से दो दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान की तीनों प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के



सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे।

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बार समवेत हुई थी लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसम्बर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान के निर्माण का कार्य पूरा होने तक इस पद पर रहे। 14 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की प्रभुत्ता सम्पन्न संविधान सभा पुनः समवेत हुई और 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से डा. भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिनों तक चली। संविधान के निर्माण कार्य पर कुल 63 लाख 96 हजार 729 रुपये का खर्च आया और इसके निर्माण कार्य में कुल 7635 सूचनाओं पर चर्चा की गई। संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे किन्तु मुस्लिम लीग द्वारा स्वयं को इससे अलग कर लिए जाने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी।

बहुत कम लोगों को ही भारतीय संविधान की पहली प्रति के बारे में मालूम होगा कि संविधान के जो सजे हुए चित्र हम देखते हैं, वह संविधान की पहली हस्तलिखित प्रति के ही चित्र हैं। इस प्रति को दिल्ली निवासी प्रेम बिहारी रायजादा ने कैलीग्राफी के जरिये तैयार किया था। 1400 पन्नों की संविधान की प्रति को अंग्रेजी में रास बिहारी ने और हिन्दी में वी के वैद्य ने लिखा, जिन्होंने इसे लिखने का कार्य एक हफ्ते में ही पूरा कर दिया था। इसी संविधान की तीन प्रतियां बनवाई गई, जिनमें से दो को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुसज्जित पन्नों पर प्रेम बिहारी रायाजादा ने, एक हिन्दी और दूसरी अंग्रेजी में तैयार किया जबकि तीसरी प्रति को अंग्रेजी में देहरादून में छपवाया गया। यह हमारे लिए आश्चर्य के साथ गौरव की भी बात है कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हुए भी भारतीय संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित ही है, जिसकी पहली दो प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी में हैं।

26 नवम्बर 1949 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाने पर तय हुआ कि संविधान की पहली प्रति को कैलीग्राफी की खूबसूरत कला में सहेजा जाए। तब पं. नेहरू ने कैलीग्राफी कला में महारत हासिल प्रेम बिहारी रायजादा से खूबसूरत लिखावट में इटैलिक अक्षरों में संविधान की प्रति लिखने का अनुरोध किया और इस तरह रायजादा ने छह महीने में इस कार्य को पूरा किया। पं. नेहरू ने प्रख्यात चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस से भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाने का आग्रह किया था और इस प्रकार 221 पृष्ठों के इस दस्तावेज के सभी 22 भागों में से प्रत्येक को एक-एक चित्र से सजाया गया और भारतीय संविधान की इस मूल प्रति पर इन 22 चित्रों को बनाने में चार साल का समय लगा। इसके प्रस्तावना पृष्ठ को नंदलाल बोस के शिष्य राममनोहर सिन्हा ने सजाया था। हमारे संविधान की मूल प्रतियों को लेकर यह तथ्य भी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि संविधान की इन बेशकीमती प्रतियों को संसद भवन की लाइब्रेरी के एक कोने में बने स्ट्रांग रूम में सहेजकर रखा गया है, जिन्हें पढ़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। संविधान की ये प्रतियां कभी खराब न हो सकें, इसके लिए इन्हें हीलियम गैस से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि हमारे देश की यह अमूल्य धरोहर हमारे पास सुरक्षित और आज भी मूल अवस्था में है। हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है, जो संविधान की प्रति के पन्नों को वातावरण के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने से रोकती है।

निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल थे, जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। अब भारत के संविधान में 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं और संविधान में अभी तक 105 बार संशोधन हो चुके हैं। संविधान में किए गए इन संशोधनों के जरिये सामयिक जरूरतों के अनुरूप जनतंत्र और शासन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए गए। संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था, जिसके तहत स्वतंत्रता, समानता एवं सम्पत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

संपादकीय

भाजपा-अकाली पुनर्मिलन

पिछले कुछ महीनों से पंजाब व दिल्ली में भाजपा व अकाली दल की तरफ से जिस तरह की बयानबाजियां और राजनीतिक हलचल सामने आ रही थी, उसके निहितार्थ स्पष्ट ही थे। जो संकेत दे रहे थे कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार साथ आना लगभग तय ही है। वर्ष 2027 के आसन्न पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन दोनों दलों का साथ आने का फैसला बताता है कि यह गठबंधन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती देने के ठोस प्रयास कर कर रहा है। इस गठबंधन की घोषणा गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर की गई है, जिसके ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक, दोनों ही तरह के महत्व हैं। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने पहली बार तीन दशक पहले भी हाथ मिलाया था। उस समय इस गठबंधन को आतंकवाद से उबरते पंजाब में हिंदू-सिख एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। कालांतर दोनों दलों के रिश्तों में खटास उस समय आई, जब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादित कानूनों के विरोध में व्यापक जनाक्रोश दिखा। किसानों के आक्रोश के चलते अकाली दल को अपना जनाधार खिसकता नजर आया था। कालांतर वर्ष 2020 में अकाली दल ने भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। बहरहाल, इस गठबंधन की घोषणा के बाद जिस तरह के बयान गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से आए हैं, वह दर्शाता है कि पिछले एक दशक में शिरोमणि अकाली दल के सिमटते जनाधार के बावजूद इस क्षेत्रीय दल को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। अमित शाह ने गठबंधन की घोषणा के बाद कहा कि अकाली दल पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। साथ ही यदि गठबंधन की जीत हुई तो मुख्यमंत्री पद अकाली दल को ही मिलेगा। वैसे यह एक हकीकत है कि इस गठबंधन के बावजूद पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देना आसान भी नहीं होगा।

वैसे आज भी शिरोमणि अकाली दल पर साल 2025 की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद हुए राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शनों का बोझ है। जिसने उस समय अकाली सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहीं, केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ तीन कृषि कानूनों को लेकर उपजे गुस्से को पूरी तरह समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए। तब किसान काफी नाराज हुए थे और उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर पूरे एक साल तक आंदोलन किया था। अंततः नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। लेकिन इसके बावजूद आगामी चुनावों में भाजपा को कोई सकारात्मक प्रतिसाद पंजाब की जनता की तरफ से नहीं मिला था। तीन माह बाद, 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिर्फ दो सीटों में ही संतोष करना पड़ा था। कमोबेश शिअद की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही थी। उसे तब सिर्फ तीन ही सीटें मिली थीं। निस्संदेह, यह अकाली दल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने तब रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। बहरहाल, भाजपा और शिअद के इस पुनर्मिलन से दो मुख्य सवाल खड़े होते हैं। क्या इस गठबंधन के पीछे पंजाब के उन्नयन को लेकर कोई साझा विज़न है? या ये फिर महज चुनावी गणित ही है? सवाल यह भी है कि क्या यह गठबंधन दोनों दलों के लिये लाभदायक साबित होगा? निस्संदेह, आज पंजाब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें आर्थिक दबाव भी एक बड़ा कारण है। राज्य गंभीर बेरोजगारी की चपेट में है। वहीं राज्य में नशीले पदार्थों का बढ़ता कारोबार व सेवन एक गंभीर चुनौती है। हालांकि, भाजपा ने पंजाब में नशे के खात्मे को अपनी प्राथमिकता बताया है और नशामुक्त पंजाब का रोडमैप भी सार्वजनिक किया है। जब पंजाब के राज्यपाल को कहना पड़ता है कि यहां गोलियां पटाखों की तरह चलती हैं, तो गैंगस्टरों के पसरे आतंक को समझा जा सकता है। शिअद और भाजपा के इस गठबंधन के लिये असली इम्तिहान यह भी होगा कि वे मतदाताओं को कैसे यकीन दिलाएंगे कि यह पंजाब के लिये सबसे बेहतर विकल्प है?

चिंतन-मनन

ईश्वर का स्वरूप क्या है?

पहले अपने स्वरूप को जानों

एक महात्मा से किसी ने पूछा- ईश्वर का स्वरूप क्या है?

महात्मा ने उसी से पूछ दिया-तुम अपना स्वरूप जानते हो?

वह बोला- नहीं जानता।

तब महात्मा ने कहा- अपने स्वरूप को जानते नहीं जो साढ़े तीन हाथ के शरीर में मैं-मैं कर रहा है और संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान परमात्मा को जानने चले हो। पहले अपने को जान लो, तब परमात्मा को तुरंत जान जाओगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को दूरबीन से देख रहा है। यदि उसे यह नहीं ज्ञान है कि वह यंत्र वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु का आकार कितना बड़ा करके दिखलाता है, तो उसे वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा?



निर्मल रानी

चुनावी महासंग्राम की राह पर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सदस्यों के लिये होने वाले आम चुनाव, फ़रवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी संभवतः फ़रवरी-मार्च 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इन सभी पाँचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त हो रहा है। इन पांच राज्यों के अलावा, वर्ष 2027 के अंत यानी नवंबर-दिसंबर में दो अन्य राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इन विधान सभा चुनावों को 2029 के प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के सेमी फ़ाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे तो इन सभी पांचों राज्यों में चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है परन्तु सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार अपनी चुनावी बिसात बिछाने वाला देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश इस बार न केवल साम्प्रदायिक बल्कि जातीय समीकरणों में भी बुरी तरह उलझ चुका है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर के बाद, निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और नाम जोड़ने व सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ़्ट मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में इस मसौदा सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 का इज़ाफ़ा हुआ है। इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 15.44 करोड़ मतदाताओं की जांच के बाद 12.55 करोड़ नाम बरक़रार रखे गए थे और लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची के भ्रम के कारण 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके मद्देनज़र भाजपा ने हर बूथ पर मतदाता जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भी मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नाम कटने के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की निगरानी के लिए सक्रिय किया है। उधर मुस्लिम समाज भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जानबूझ कर पूर्व नियोजित तरीक़े से एक बड़ी साज़िश के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायत कर रहा है।



उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां भाजपा बनाम इण्डिया गठबंधन (कांग्रेस+समाजवादी पार्टी) चुनावी मुक़ाबला होने की संभावना थी वहीँ मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शुरू से ही अपनी डफ़ली अलग ही बजा रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक इसे मायावती द्वारा भाजपा को लाभ पहुँचाने की कोशिश की नज़र से भी देख रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की ए आई एम आई एम ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रेशखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) से चुनाव पूर्व समझौता कर उत्तर प्रदेश के राजनैतिक हल्क़ों में खलबली पैदा कर दी है। बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना पर जहां पहले भी चर्चा होती रही है वहीँ चुनाव नज़दीक आने पर बने ओवैसी चंद्रशेखर के यह नये समीकरण व इसके द्वारा उठाये जाने वाले धर्मस्थल विध्वंस,लक्षित एस आई आर,अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, धार्मिक जुलूसों जैसे अनेक ऐतिहासिक विवादों पर तीखे बयान सामाजिक और साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को और भी बढ़ा रहे हैं। गोया उत्तर प्रदेश के लगभग 19-20त्न मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को लेकर एक ओर जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन इस वोट बैंक को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे थे वहीं असदुद्दीन ओवैसी के ए आई एम आई एम व चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) और बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक तो पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के हितसाधक नेता के रूप में देखते आ रहे थे परन्तु अब इस सूची में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी शामिल हो गया है।

उधर भाजपा समर्थित बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जोकि पहले भी अपने सम्प्रदायिकपूर्ण व विवादित बयानों के लिये चर्चा में बने रहते हैं उन्होंने पिछले दिनों हमारे राम तुम्हारे कृष्ण जैसी बातें कर और साथ ही भगवान कृष्ण को लेकर अशोभनीय बातें कर समाज में रोष भड़का दिया है। इसके बाद बेशक धीरेन्द्र शास्त्री ने मुआफ़ी मांग ली है परन्तु उनके समर्थन और विरोध को लेकर खिंची रेखायें साफ़ दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजनीति में ब्राह्मण लॉबी और राजपूत/ठाकुर असंतोष जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के कोर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा, भाजपा और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के बीच होड़ देखी जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम जन्म भूमि आंदोलन का पूरा लाभ उठा लेने के बाद और साथ ही मंदिर के दान व चंदा चोरी जैसे आरोपों में घिरने के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाये जाने के भी चर्चा सुनी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि अधिकांश दलों द्वारा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उप-जातियों के आधार पर टिकट वितरण और प्रचार से स्थानीय स्तर पर जातीय वैमनस्य भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनावों के बीच डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं और भड़काऊ कंटेंट के प्रसार से भी साम्प्रदायिक और जातीय तनाव भड़कने का जोखिम बना रहता है। इसीलिये 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने के कारण इस चुनाव में आक्रामक बयानबाज़ी बढ़ने की पूरी आशंका है। जबकि एक अध्ययन के मुताबिक़, सभी समुदायों के युवा मतदाता पहचान की राजनीति के साथ-साथ रोज़गार, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश, चुनावी महासंग्राम की राह पर जाता दिखाई दे रहा है।

बिहार की बदलती तस्वीर विकास की नई राह पर आगे बढ़ता राज्य



कांतिलाल मांडोत

घोटालों और पिछड़ेपन की पहचान से बाहर निकलकर निवेश शिक्षा रोजगार और सुशासन की ओर बढ़ता बिहार

बिहार का नाम आते ही कभी राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन और बदहाल व्यवस्था की चर्चा होने लगती थी। एक समय ऐसा भी था जब बिहार की पहचान विकास की संभावनाओं से अधिक राजनीतिक विवादों और कानून व्यवस्था की चुनौतियों के कारण बनती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य की तस्वीर बदलने के प्रयासों ने विकास की एक नई उम्मीद पैदा की है। सड़क, बिजली, पुल, शिक्षा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में हो रहे काम इस बात का संकेत हैं कि बिहार अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को वैशाली दौरा और लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास इसी बदलती सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

बिहार की प्रगति को केवल राजनीतिक नारों के आधार पर नहीं परखा जा सकता। इसके लिए जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों को समझना जरूरी है। गंगा नदी पर बना नीतीश सेतु इसका बड़ा उदाहरण है। लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 19.7 किलोमीटर लंबी छह लेन की यह परियोजना पटना और वैशाली के बीच आवागमन को आसान बनाएगी। इससे राघोपुर दियारा के लाखों लोगों को बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा। पहले जिन लोगों को नाव और पीपा पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता था, उन्हें अब बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। किसानों के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। यह केवल एक पुल नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आर्थिक संपर्क मजबूत करने वाला माध्यम है।

बिहार की बदलती तस्वीर में बिजली क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बक्सर के चौसा ताप विद्युत संयंत्र की दूसरी 660 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। पीरपैंती बिजली परियोजना के लिए पारेषण व्यवस्था और नवादा के फुलवरिया बांध पर तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए 1,130 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने की योजना कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। हालांकि इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिजली गांवों और खेतों तक नियमित रूप से पहुंचती है या नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में निवेश और विकास की चर्चा करते हुए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बिहार घोटालों के कारण चर्चा में रहता था, जबकि अब निवेश और विकास परियोजनाओं की बात होती है। इस राजनीतिक टिप्पणी के पीछे एक महत्वपूर्ण सवाल भी है कि क्या बिहार वास्तव में अपनी पुरानी आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकल रहा है? इसका उत्तर अभी पूरी तरह हां में देना जल्दबाजी होगी, लेकिन बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़क संपर्क और बिजली उत्पादन में विस्तार सकारात्मक संकेत अवश्य हैं।

बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार और युवाओं का पलायन रोकने की है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह में कहा कि दुनिया को केवल विश्वविद्यालयों से निकले स्नातक नहीं, बल्कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित कुशल कामगारों की भी आवश्यकता है। उनका यह संदेश बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है। राज्य में बड़ी युवा आबादी है। यदि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक उद्योगों और स्थानीय रोजगार से जोड़ा जाए तो बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होगी। सेमीकंडक्टर, बिजली उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशनी होंगी। केवल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बांटने से रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योगों की स्थापना और बाजार की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देना होगा। अब सवाल कानून व्यवस्था का है। क्या बिहार में अपराध पूरी तरह समाप्त हो गया है? इसका उत्तर नहीं है। पिछले वर्षों में गंभीर अपराधों में गिरावट के संकेत मिले हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 2024 की तुलना में हत्या के मामलों में 8.3 प्रतिशत, दुष्कर्म में 8.2 प्रतिशत और डकैती में 26.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह सकारात्मक उपलब्धि है। लेकिन दूसरी ओर चोरी, साइबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां अब भी चिंता का विषय हैं। इसलिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त मानकर संतुष्ट हो जाना उचित नहीं होगा। पुलिस की जवाबदेही, त्वरित न्याय, महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण से दूर रखना सुशासन की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार में परिस्थितियां बदली हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार विकास और निवेश को अपनी प्राथमिकता बता रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के सामने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिली पराजय के बाद उसे आत्ममंथन करने की जरूरत है। केवल जातीय समीकरण, राजनीतिक आरोप और सत्ता विरोधी बयानबाजी के सहारे जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। विपक्ष का दायित्व है कि वह बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे तथा उनके समाधान का व्यावहारिक विकल्प भी प्रस्तुत करे। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है, इसलिए उसकी कमजोरी अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ बुनियादी प्राथमिकताओं पर गंभीरता से काम करना होगा। गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। उद्योगों को जमीन, बिजली और बेहतर परिवहन सुविधा के साथ पारदर्शी प्रशासन देना होगा। सरकारी नौकरियों की भर्ती समय पर होनी चाहिए और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पंचायत से लेकर सचिवालय तक सरकारी योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही तय करनी होगी। कृषि के साथ छोटे उद्योगों और महिला उद्यमिता को भी आर्थिक विकास का आधार बनाना होगा। बिहार बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव को स्थायी और व्यापक बनाना अभी बाकी है। पुलों का निर्माण, बिजली परियोजनाएं और हजारों करोड़ रुपये का निवेश विकास की मजबूत नींव बन सकते हैं। असली परीक्षा तब होगी जब बिहार का युवा रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर नहीं होगा, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आम नागरिक बिना भय के जीवन जी सकेगा। सुशासन का अर्थ केवल अपराधियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, सुरक्षा और अवसर उपलब्ध कराना है। बिहार के पास प्रतिभा, श्रमशक्ति और अपार संभावनाएं हैं। जरूरत ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति की है जो विकास को चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला जनकल्याणकारी अभियान बनाए। तभी बिहार की बदलती तस्वीर वास्तव में विकसित बिहार की पहचान बन सकेगी।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस : भारत की डेयरी शक्ति और किसान समृद्धि का उत्सव

भारत की पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में दुग्ध

बिहान भारत

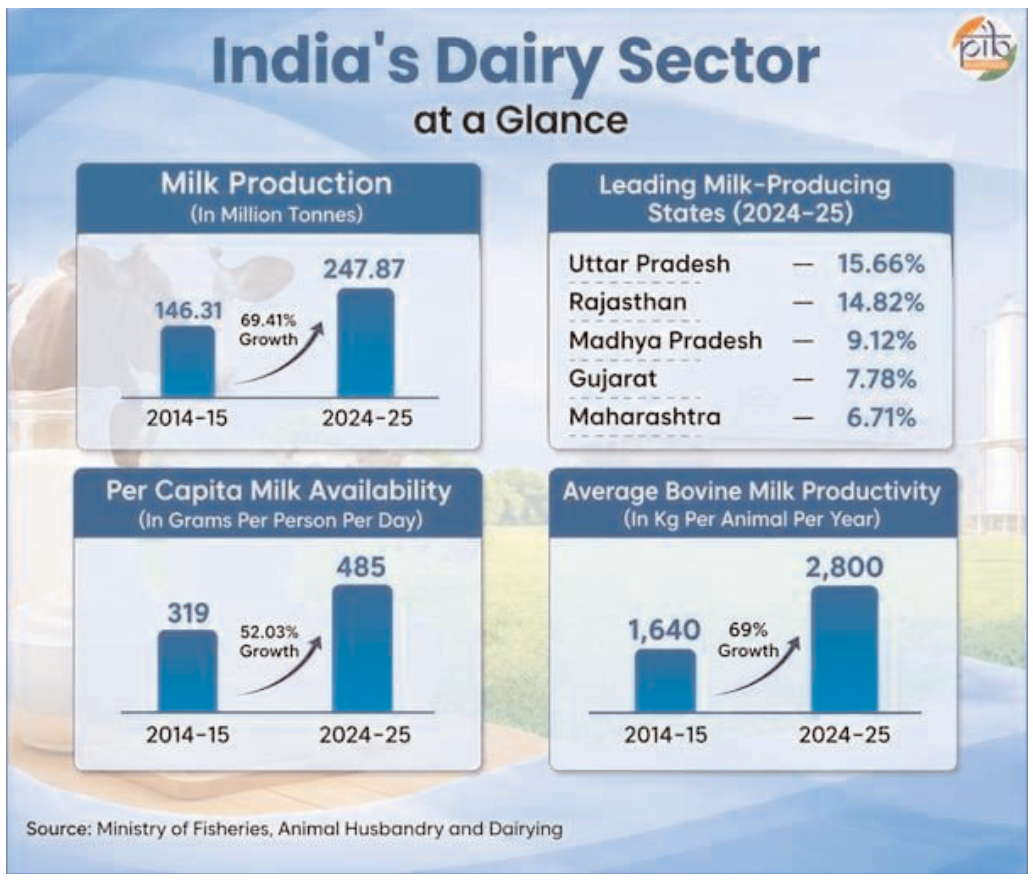

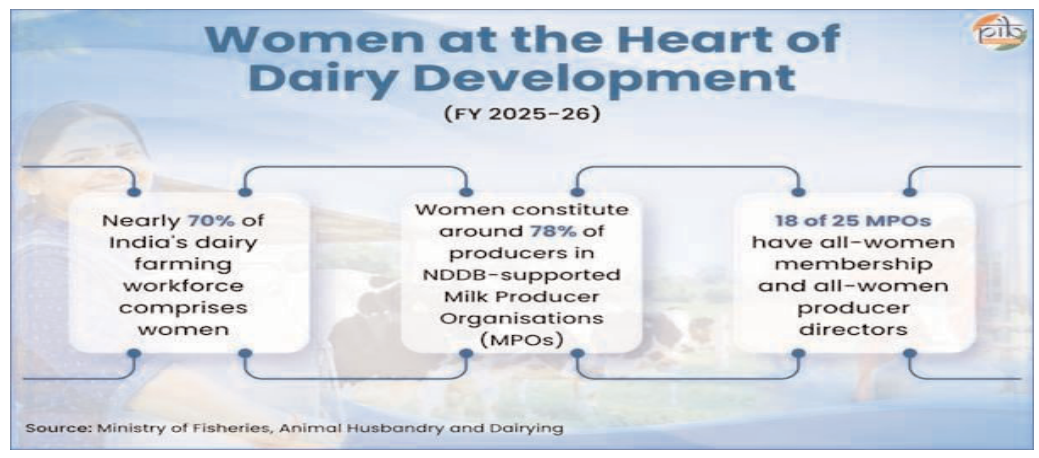

देश के पोषण परिदृश्य में दुग्ध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम प्रदान करता है, जो आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में होते हैं। अक्सर दूध को लगभग पूर्ण भोजन माना जाता है, सभी आयु वर्गों में विकास, हड्डियों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रदान करता है।

भारत लगातार विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना हुआ है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग एक-चौथाई योगदान देता है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2024-25 के बीच, उत्पादन 5.41 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जो 247.87 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण आयाम भी है। डेयरी 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है, जिसमें महिलाएं दुग्ध उत्पादन और संग्रह में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। भारत के डेयरी उत्पादन कार्यबल का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं हैं, जो इस क्षेत्र की वृद्धि में उनके योगदान और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को उजागर करता है।

प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीस कुरियन की जयंती का स्मरण करता है, जो देश की श्वेत क्रांति के जनक थे। यह दिन भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन में उनके परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता देता है। यह उन लाखों डेयरी किसानों को सम्मानित करता है जिनके प्रयास देश के दुग्ध उत्पादन में नेतृत्व को बनाए रखते हैं।

भारत के डेयरी क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

भारत ने उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनने की स्थिति बनाए रखी है।

दुग्ध उत्पादन 69.41 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया।

प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (15.66 प्रतिशत), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत), और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत) थे। ये पांच राज्य देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 54.09 प्रतिशत थे।

प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 52.03 प्रतिशत बढ़ी, जो वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 319 ग्राम थी, और वर्ष 2024-25 में 485 ग्राम हो गई।

औसत गौ दुग्ध उत्पादकता 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,640 कि.ग्रा. से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,800 कि.ग्रा. प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई, जो 69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था के पीछे सहकारी शक्ति

भारत का डेयरी सहकारी आंदोलन दुग्ध उत्पादकों के लिए एक संगठित मंच प्रदान करता है। यह गांव स्तर की समितियों को जिला दुग्ध संघों और राज्य संघों से जोड़ता है। ये संस्थान दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और डेयरी सेवाओं तक पहुंच का सहयोग करते हैं।

देश का डेयरी सहकारी नेटवर्क शामिल है:

22 दुग्ध संघ
241 जिला सहकारी दुग्ध संघ
28 मार्केटिंग डेयरी
25 दुग्ध उत्पादक संगठन
लगभग 2.45 लाख गांवों और 1.65 करोड़ डेयरी किसानों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया

यह नेटवर्क ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों और संगठित डेयरी बाजारों के बीच एक संस्थागत संबंध प्रदान करता है। यह सामूहिक विपणन और बेहतर संगठित दुग्ध खरीद प्रणालियों तक पहुंच का भी समर्थन करता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के डेयरी सर्विसेज

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड-एनडीडीबी ने भारत में किसान-स्वामित्व वाली डेयरी संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी सहायक कंपनी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीडीबी-डीएस), दुग्ध उत्पादक संगठनों (एमपीओ) के निगमन और संचालन को सुगम बनाती है।

एमपीओ किसान-स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियां होती हैं जो दुग्ध उत्पादकों को पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थानों में संगठित करती हैं। वे सामूहिक दुग्ध खरीद को सुविधाजनक बनाती हैं, बाजार संबंधों को मजबूत करती हैं, और किसानों को पारदर्शी मूल्य निर्धारण और सीधे बैंक भुगतान तक पहुंच प्रदान करती हैं।

31 अक्टूबर 2026 तक, एनडीडीबी-डीएस ने सफलतापूर्वक 25 एमपीओ स्थापित किए हैं।

इन 25 एमपीओ में से 18 में सभी महिला सदस्य हैं, और महिलाएं अपने-अपने बोर्ड में निमार्ता निदेशक के रूप में कार्य करती हैं।

ये संगठन 12 राज्यों के 175 जिलों में 13 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को कवर करते हैं।

इन संगठनों में उत्पादकों में लगभग 78 प्रतिशत महिलाएं हैं।

एमपीओ प्रतिदिन लगभग 70 लाख लीटर दुग्ध खरीदते हैं।

डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद और बिक्री

डेयरी सहकारी समितियाँ किसानों के लिए एक संगठित बाजार प्रदान करती हैं और दुग्ध की नियमित खरीद सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। खरीद मूल्य सहकारी समितियों और अन्य डेयरी द्वारा उत्पादन लागत और बाजार की स्थितियों के आधार पर तय किए जाते हैं। कई डेयरी सहकारी समितियां स्वचालित दुग्ध संग्रह और भुगतान प्रणालियों का उपयोग करती हैं। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

31 अक्टूबर 2026 तक, डेयरी सहकारी समितियों ने दर्ज किया:

690.90 लाख किलोग्राम प्रति दिन दुग्ध की खरीद।
462.95 लाख लीटर प्रति दिन तरल दुग्ध की बिक्री।

डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक नई गति

श्वेत क्रांति 2.0, सहकारी नेतृत्व वाली पहल जिसे 25 दिसंबर 2024 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया (एसओपी 19 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया), का उद्देश्य असममिलित गांवों और पंचायतों में डेयरी सहकारी कवरेज का विस्तार करना है। यह अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद को 50 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखता है । यह पहल सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने, बाजार तक पहुंच सुधारने, रोजगार सृजन और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अंतर्गत वित्तपोषित हैं।

वर्ष 2028-29 तक, इस पहल का लक्ष्य असम्मिलित गांवों और पंचायतों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना और 46,422 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करना है।

31 अक्टूबर 2026 तक श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत प्रगति,

24,097 नई डेयरी सहकारी समितियाँ बनाई गईं।
31,394 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत किया गया।

डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और चक्रीयता

श्वेत क्रांति 2.0 डेयरी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और चक्रीयता को बढ़ावा देता है। यह जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं, कुशल संसाधन उपयोग और नवीकरणीय, कम उत्सर्जन समाधानों को प्रोत्साहित करता है। यह पहल 'कूड़े से सोना' (मवेशी गोबर और कृषि अवशेषों को बायोगैस, जैविक खाद, और मूल्य-वर्धित जैव-उर्वरकों में बदलना) की दृष्टि को दो बहु-राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से आगे बढ़ाती है:

कॉपरेटिव इनपुट और सर्विस डिलीवरी मल्टी-स्टेट लिमिटेड: इसका उद्देश्य गुणवत्ता इनपुट और सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें पशु चारा, रोग नियंत्रण, और कृत्रिम गभार्धान शामिल हैं।

गोमय सहकारी समिति मल्टी-स्टेट लिमिटेड: यह गोबर के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग पर केंद्रित है। गोबर्धन, राष्ट्रीय सर्कुलर जैव ऊर्जा योजना, जो 01 अक्टूबर, 2026 को शुरू की गई, भारत की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास में बदलने का लक्ष्य रखती है। 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू की जाएगी।

यह सुनिश्चित ऑफटेक, स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और क्रेडिट समर्थन के माध्यम से डोमेस्टिक कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने का प्रयास करता है। यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, निजी निवेश को सक्रिय करेगा और सर्कुलर बायोइकोनॉमिक को बढ़ावा देगा। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर्धन) पहल मूल रूप से वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह जैविक कचरे, जिसमें मवेशी के गोबर और कृषि अवशेष शामिल हैं, को बायोगैस और बायो-स्लरी में परिवर्तित करने को बढ़ावा देती है, जिससे गांव की सफाई, कचरा प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका में सहयोग मिलता है।

ये पहलें संसाधन चक्रीयता को मजबूत करती हैं और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करती हैं।

मजबूत डेयरी इकोसिस्टम का निर्माण

भारत का डेयरी क्षेत्र मजबूत अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रजनन, गुणवत्तापूर्ण चारा और सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल पर निर्भर करता है। सरकारी पहल इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करती हैं, पशुपालन उत्पादकता बढ़ाती हैं, पशु स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और डेयरी किसानों को लाभ देती हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का उद्देश्य देश भर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना है। यह दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और दुग्ध गुणवत्ता अवसंरचना का समर्थन करता है। यह कार्यक्रम डेयरी क्षेत्र के संतुलित विकास को दो घटकों के माध्यम से बढ़ावा देता है:

घटक क: दुग्ध खरीद और गुणवत्ता अवसंरचना को सुदृढ़ करना

यह संगठित दुग्ध खरीद नेटवर्क का विस्तार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह गांव स्तर की कोल्ड चेन, दुग्ध परीक्षण सुविधाओं, और गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर प्रशिक्षण का भी समर्थन करता है।

घटक ख: सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी

किसानों की संगठित बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाकर दुग्ध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करता है। यह डेयरी प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना का समर्थन करता है और किसानों के आय में सुधार के लिए उत्पादक-स्वामित्व वाली संस्थाओं को सुदृढ़ करता है। घटक ख नौ राज्यों में लागू किया गया है: आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

31 अक्टूबर, 2026 तक एनडीडीडी की भौतिक उपलब्धियां

40,800 नई डेयरी सहकारी समितियां संगठित/पुनर्जीवित की गईं।
25.82 लाख अतिरिक्त किसान नामांकित हुए और 161.17 लाख अतिरिक्त दुग्ध खरीद की गई।
168 लाख लीटर प्रति दिन दुग्ध ठंडा करने की क्षमता बनाई गई।
94,000 दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण उपकरण वितरित किए गए।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जो विशेष रूप से स्वदेशी गोवंशीय नस्लों के वैज्ञानिक समग्र विकास और संरक्षण के लिए है। यह योजना दुग्ध उत्पादन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ताकि दुग्ध की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। मार्च 2025 में संशोधित, यह योजना प्रजनन अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उन्नत प्रजनन तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देती है। इसके हस्तक्षेपों में वीर्य स्टेशनों को मजबूत करना, कृत्रिम गभार्धान सेवाओं का विस्तार करना, और लिंग-सॉर्टेड वीर्य और आईवीएफ तकनीक जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से नस्ल सुधार को तेज करना शामिल है।

आरजीएम के अंतर्गत प्रगति

ग्रामीण भारत में 50,023 बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गभार्धान तकनीशियन प्रशिक्षित और सुसज्जित।
24 इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रयोगशालाएं स्थापित।
48 वीर्य स्टेशनों को मजबूत किया जा रहा है।
32 हेफर पालन केंद्र स्वीकृत।
देशव्यापी कृत्रिम गभार्धान कार्यक्रम (एनएआईपी)
यह कार्यक्रम कृत्रिम गभार्धान कवरेज को बढ़ाना और उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों सहित स्वदेशी नस्लों के वीर्य के साथ किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गभार्धान सेवाएं प्रदान करना चाहता है।
18.71 करोड़ से अधिक कृत्रिम गभार्धान किए गए।
लगभग 11.17 करोड़ जानवरों को कवर किया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों में आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और कोल्ड-चेन अवसंरचना का समर्थन करता है।
यह पात्र लाभार्थियों को 8 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के माध्यम से 258 डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों को निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों के लिए वर्ष 2020-21 से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ समर्थन मिला है। इससे लगभग 21,797 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
500.58 लाख लीटर प्रति दिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता और मूल्यवर्धन क्षमता के साथ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का समर्थन करता है। यह पशु चिकित्सा अवसंरचना को भी मजबूत करता है और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से घर-घर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।
31 अक्टूबर 2026 तक, 4,019 एमवीयू 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत थे।
इन इकाइयों ने लगभग 1.5 करोड़ किसानों को घर-घर सेवाएं प्रदान की हैं और लगभग 3.3 करोड़ पशुओं का उपचार किया है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो एमएचडीसीपी का एक घटक है, फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) नियंत्रण और अंततः उन्मूलन का समर्थन करता है, साथ ही टीकाकरण और निगरानी के माध्यम से ब्रुसेलोसिस नियंत्रण भी करता है।
31 अक्टूबर 2026 तक, कुल एफएमडी टीकाकरण 152 करोड़ से अधिक खुराकों तक पहुंच गया, जिससे लगभग 8 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।
एफएमडी प्रकोप 2019 में 132 से घटकर 2025 में 40 रह गए।
ब्रुसेलोसिस के प्रकोप 2019 में 22 से घटकर 2025 में 15 हो गए।

भारत पशुधन के माध्यम से डिजिटल पशुधन रिकॉर्ड

पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से ₹भारत पशुधन₹ डेटाबेस विकसित किया है। भारत पशुधन डेटाबेस में पंजीकृत जानवरों की पहचान एक अनूठे 12-अंकीय ईयर-टैग नंबर के माध्यम से की जाती है, जिसे ₹पशु आधार₹ के नाम से जाना जाता है। यह जानवरों पर किए गए सभी प्रकार के लेन-देन जैसे टीकाकरण, प्रजनन, उपचार आदि को पंजीकृत करने के लिए एक प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है। यह डेटाबेस पहचाने गए जानवरों का डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करता है और पशुधन प्रबंधन का समर्थन करता है।
31 अक्टूबर 2026 तक, 9,98,55,955 पशुधन मालिकों का पंजीकरण किया गया है।
39.42 करोड़ से अधिक पशु आधार जारी किए गए हैं।

वैश्विक बाजारों में भारतीय डेयरी उत्पाद

भारत का डेयरी क्षेत्र एक बड़े घरेलू बाजार की सेवा करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
भारत ने वर्ष 2025-26 के दौरान 97,524.82 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का निर्यात किया।
वर्ष के दौरान निर्यात आय 407.12 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई।
प्रमुख निर्यात गंतव्यों में यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और बहरीन शामिल थे।
ये निर्यात भारत के डेयरी उत्पादों की पहुंच को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दर्शाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की उपस्थिति घरेलू खपत से परे भी बढ़ती है।

हर बूंद के पीछे की ताकत

भारत की डेयरी यात्रा लाखों किसानों, महिलाओं और सहकारी संस्थानों के योगदान को दर्शाती है। बढ़ता हुआ दुग्ध उत्पादन, मजबूत अवसंरचना, वैज्ञानिक प्रजनन और बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवा इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करती रहती है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीस कुरियन की विरासत का सम्मान करता है और उन किसानों को मान्यता देता है जिनके प्रयास भारत के डेयरी नेतृत्व को बनाए रखते हैं, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करते हैं और राष्ट्र की पोषण सुरक्षा में योगदान देते हैं।

असम में डीआईजी और एसएसपी में जमकर हुई मारपीट

● सीएम ने पल्ला झाड़ा कहा- ये आपस का मामला है

कोकराझार, एजेंसी। असम के कोकराझार जिले में देर रात आयोजित एक पार्टी के दौरान दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कोकराझार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अक्षत गर्ग घायल हो गए हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे निजी विवाद बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना पिछले वीकेंड की है। कोकराझार के सराईखोला स्थित सातवीं असम पुलिस बटालियन परिसर में अक्षत गर्ग ने एक पार्टी का आयोजन किया था। इसी दौरान अक्षत गर्ग और वेस्टर्न रेंज के डीआईजी वाईटी ग्यात्सो के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें एसएसपी अक्षत गर्ग को कई चोटें आईं। हालांकि, असम पुलिस मुख्यालय ने अभी तक इस कथित घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई बयान जारी किया है। घटना किन परिस्थितियों में हुई और पार्टी में मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका थी, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है, लेकिन यह एक निजी पार्टी में हुआ विवाद था और उस समय दोनों अधिकारी ड्यूटी पर नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह घटना ड्यूटी के दौरान हुई होती तो सरकार हस्तक्षेप करती और जरूरी कदम उठाती, लेकिन निजी मामले में सरकार कुछ नहीं कह सकती।

दलाई लामा को लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला

● विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर किया आवंटन, तिब्बती नेतृत्व ने फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को राजधानी दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में सरकारी आवास आवंटित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर दलाई लामा के कार्यालय 'गादेन फोडरंग ट्रस्ट' को पंडित रविशंकर शुक्ला लेन स्थित टाइप-7 सरकारी बंगला आवंटित किया है। हालांकि, इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी आवास का आवंटन आम तौर पर तीन वर्ष के लिए किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसकी अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी होता है। इस आवास से दलाई लामा के दिल्ली दौरों के दौरान उनके ठहरने के लिए एक स्थायी व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संसद की स्पीकर डोलमा त्सेरिंग ने इसे अच्छी खबर बताते हुए कहा कि इससे दलाई लामा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आना और यहां ठहरना अधिक सुविधाजनक होगा। निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति के सदस्य चोदक ग्यात्सो ने भी फैसले को सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों के पास अपना देश नहीं होने के दौर में भारत ने उन्हें शरण दी और धर्मशाला में बसने, स्कूल तथा अन्य संस्थान स्थापित करने में सहयोग किया। उनके मुताबिक, इन संस्थानों ने तिब्बती संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



मणिपुर में केसीपी से जुड़े पांच उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सुरक्षा बलों ने पिछले दो दिनों में अलग-अलग अभियानों के दौरान प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीडब्ल्यूजी) से जुड़े पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अभियान के दौरान हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस कमांडो और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने सोमवार को पटसोई थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की।

बीजेपी-अकाली दल गठबंधन को सचिन पायलट ने बताया, हताशा का गठबंधन

-कहा- दोनों दलों के अलग होने के कारण आज तक स्पष्ट नहीं, जनता तय करेगी बेहतर विकल्प

चंडीगढ़ , एजेंसी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के फिर साथ आने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट ने दोनों दलों के गठबंधन को 'हताशा का गठबंधन' बताया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में दोनों दलों के लिए राजनीतिक जगह नहीं बची है।



भाजपा और अकाली दल ने मंगलवार को गठबंधन की घोषणा की थी। छह साल बाद शिअद की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में मुख्यमंत्री पद शिरोमणि अकाली दल के पास रहेगा और वह 'बड़े भाई' की भूमिका में होगा।

पायलट ने कहा कि यह समझौता और हताशा का गठबंधन है, क्योंकि दोनों दलों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि छह साल पहले वे किन कारणों से अलग हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि वे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से भाजपा और शिअद ने अपना पुराना गठबंधन तोड़ा था।

उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी दी है और क्या तीन कृषि कानूनों को लेकर माफी मांगी गई है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर जान गंवाने वाले किसानों के प्रति अकाली दल के रुख पर भी सवाल उठाया।

पायलट ने कहा कि दोनों दलों का फिर साथ आना उनकी अपनी पसंद है और जनता ही तय करेगी कि उसके लिए बेहतर विकल्प कौन है। गौरतलब है कि शिअद ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर भाजपा के साथ अपना 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे।

सेना पर हमले की थी साजिश में आतंकी वांटेड उजैद गिरफ्तार

● बम वाली जैकेट पहनकर आर्मी का चेकपोस्ट उड़ाने का था प्लान

मेरठ, एजेंसी। यहां एक बड़ी कार्रवाई के तहत जम्मू-कश्मीर से वांटेड संदिग्ध आतंकी उजैद को स्क्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर उजैद और उसके साथी किशोरों को आत्मघाती आतंकी (फिदायीन) बनाने का मॉड्यूल चला रहे थे। इनका मकसद जम्मू-कश्मीर में आर्मी कैंपों और आर्मी काफिले पर उरी और पुलवामा जैसे बड़े हमले करना था। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बनियापाड़ा, कोतवाली मेरठ निवासी उजैद की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वह फिदायीन हमलों में इस्तेमाल होने वाली एक्सप्लोसिव जैकेट लेने के लिए गुरैज वैली के रास्ते पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था। उजैद उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जिसका खुलासा पिछले साल नवंबर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था। उस दौरान साजिद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उजैद पिछले 10 माह से फरार चल रहा था। उजैद और साजिद सहित कुछ युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई एजेंट के संपर्क में आए थे। इन्हें किशोरों को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करने और आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने का टास्क दिया गया था। पकड़ा गया उजैद पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर, तारिक मसूद और डॉ इशरार का प्रशंसक था और उनके वीडियो देखता था। इन्हीं वीडियो पर कमेंट करने के दौरान वह पाकिस्तानी हैंडलर की नजर में आया। इंस्टाग्राम, सेशन ऐप और सिग्नल ऐप पर 'ट्यूशन-40' और 'ब्रिगेड' नाम से ग्रुप बनाकर उजैद और अन्य को जोड़ा गया था। इन ग्रुपों में पीओके से आतंकी अमीर हमजा, पाकिस्तान के पंजाब से अबू मुसाब और पीओके से फुरकान व कामरान जैसे कई आईएसआई एजेंट जुड़े थे। इन ऐप्स पर बने ग्रुपों में ही हमलों की योजना बनाई गई थी। सेशन ऐप पर बने 'ब्रिगेड' ग्रुप में साजिद ने लिखा था कि वह बम वाली जैकेट पहनकर आर्मी का चेकपोस्ट उड़ा देगा, और 100 प्रतिशत देगा। दूसरे साथी द्वारा जैकेट के बारे में पूछने पर पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर ने जवाब दिया था कि वे इसे घर में ही बना लेंगे।

सीजेपी नेता सौरभ दास की विदेश यात्रा पर रोक

● दीपके की फॉड सलाह पर छिड़ा विवाद

नई दिल्ली, एजेंसी। काम्पैक्ट जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास को विदेश यात्रा से रोके जाने पर विवाद गहरा गया है। इस घटना के बाद पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सरकार पर तंज कसते हुए दास को कोई बड़ा फ्रॉड करने की सलाह दे डाली, ताकि उन्हें भी नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों की तरह देश से बाहर जाने दिया जाए। दीपके ने दास के पासपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ दास ने सोमवार को आरोप लगाया था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के बुलावे पर लंदन जाने से रोका गया है। उन्होंने एक वीडियो साझा कर बताया कि उन्हें पैनल चर्चा और लेक्चर के लिए न्योता मिला था, लेकिन सरकार ने उन्हें यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया। सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, विजय माल्या ने 9 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड किया, नीरव मोदी ने 6 हजार 498 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया, और मेहुल चोकसी ने 7 हजार 80 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया। इन सभी तीनों को देश छोड़कर भागने दिया गया। सौरभ दास भाई, कोई बड़ा फ्रॉड कर अगर बाहर जाना है तो। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि काश सौरभ ने बैंक लूटा होता या फ्रॉड किया होता, फिर सरकार उसे जरूर लंदन जाने देती। दीपके ने सौरभ दास के पासपोर्ट के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किया। उन्होंने लिखा, सौरभ के पासपोर्ट में गड़बड़ियां? उसका पासपोर्ट तो इसी सरकार ने साल 2019 में जारी किया था। उन्हें 7 साल से कोई गड़बड़ियां नहीं मिली हैं, लेकिन सीजेपी के गठन और सौरभ दास के उसके सबसे बड़े चेहरों में से एक बनने के बाद अचानक मिलने लगीं। उन्होंने यह भी कहा कि दास को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और बताया गया कि वह भारत से बाहर नहीं जा सकता। दीपके ने प्रश्न किया, एक भारतीय विदेश यात्रा क्यों नहीं कर सकता? क्या वह अपराधी है? दास द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने कोई घोटाला या धोखाधड़ी नहीं की। दास ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनियन में 1 दिसंबर को था, जिसमें उन्हें और सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह को आमंत्रित किया गया था। छात्रों ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और क्वीन मैरी विश्वविद्यालय में भी अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई थी।

पश्चिम बंगाल: तेजी से बढ़ा एनसीपीआई का दबदबा, टीएमसी में फिर टूट

कोलकाता , एजेंसी । पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी समीकरण आकार ले रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कभी मजबूत गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में अब नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। इस पार्टी में पहले से ही सायोनी घोष, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान जैसे चर्चित नेता शामिल हो चुके हैं। तृणमूल के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के बाद अब पंचायत स्तर पर भी पार्टी का विस्तार हो रहा है।

उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक कई पंचायत प्रतिनिधियों के पाला बदलने से ममता बनर्जी के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हो गई है। इस घटनाक्रम ने जहां टीएमसी के ग्रामीण आधार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।

इस बदलाव की सबसे अहम बात यह है कि एनसीपीआई कोई पुरानी या बंगाल में मजबूत संगठनात्मक आधार वाली पार्टी नहीं है। यह केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। इसके बावजूद पंचायतों में लगातार हो रहे दलबदल ने उसे राज्य की राजनीति में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एनसीपीआई का यह उत्थान चौंकाने वाला है, क्योंकि हाल तक पश्चिम बंगाल में इसकी न के बराबर संगठनात्मक उपस्थिति थी। तृणमूल कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद मची राजनीतिक उथल-पुथल का यह सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। इसने बड़ी संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और कई ग्रामीण निकायों में सत्ता का संतुलन बदल दिया है। ताजा घटनाक्रम में सबसे बड़ा असर उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।

एनसीपीआई का दावा है कि उसने तृणमूल के कब्जे वाली 13 ग्राम पंचायतों और दो पंचायत समितियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस इलाके में संदेशखाली और मीनाखान जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां से कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। मीनाखान पंचायत समिति में 23 सदस्यों में से 13 ने तृणमूल छोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया, जिनमें समिति के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। इसी तरह संदेशखाली-ढ़ढ़ पंचायत समिति के 24 सदस्यों में से 17 ने एनसीपीआई का रुख किया है, जबकि संदेशखाली-ढ़ की नजात-2 ग्राम पंचायत में 26 में से 19 सदस्य पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले की गोलपोखर-द्वितीय पंचायत समिति में भी अध्यक्ष समेत 16 सदस्य एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं।



एनसीपीआई का यह विस्तार तृणमूल की चुनावी हार और उसके बाद पार्टी के संसदीय खेमे में हुई टूट के बाद हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के 27 लोकसभा सदस्यों में से 20 सदस्य अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हो गए थे, साथ ही उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस ने एनसीपीआई को भाजपा के मोहरे के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा, भाजपा अपनी बी-टीम और सी-टीम ला रही है। जो लोग दल बदलकर गए हैं, वे भाजपा के एजेंट हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी आरोप लगाया कि एनसीपीआई का सामने आना, बंगाल में भाजपा के विस्तार को आसान बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

संविधान दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस की रैली आज, खड़गे होंगे शामिल

● प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम, आराधना मिश्रा बोलीं—संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प मजबूत करेंगे

लखनऊ,एजेंसी। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को लखनऊ में कांग्रेस की ओर से रैली और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम में शामिल होना प्रदेश कांग्रेस के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे कांग्रेस सड़क से लेकर प्रदेश स्तर तक और मजबूत करेगी। इसी संकल्प के साथ 26 नवंबर को रैली आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि करीब साढ़े तीन घंटे तक बैठक हुई और बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने इसे गठबंधन के लिए अच्छी शुरुआत बताया। मिश्रा ने कहा कि गठबंधन को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 30 फीसदी तक बढ़ाएगी केरल सरकार

-महिला अधिकारी मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में कर रही अच्छा प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरलम सरकार ने राज्य में अपराध पर लगाम लगाने और जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए पुलिस बल में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बताया कि सरकार चरणबद्ध भर्ती के जरिए पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को 30 फीसदी तक बढ़ाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले के तहत, भविष्य में होने वाली भर्तियों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:3 रखा जाएगा। मंत्री ने मलप्पुरम अपराध शाखा इकाई कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला अधिकारी अपराध का पता लगाने और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में राज्य भर के 63 थानों में एसएचओ के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही अपराध शाखा और सतर्कता शाखाओं की कार्यकुशलता में सुधार के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। गृह मंत्री ने बताया कि अपराध शाखा और सतर्कता विभाग में अब नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। जांच में रुचि और दक्षता रखने वाले अधिकारियों का चयन विशेष परीक्षा के जरिए किया जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह परीक्षा पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के परामर्श से तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन विशेष शाखाओं का उद्देश्य नियमित पुलिस बल में काम के बोझ के कारण दरकिनार कर दिए गए अधिकारियों को जगह देना नहीं है।

वर्तमान में राज्य में अपराध शाखा फिलहाल 2,763 अहम मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 321 मामले अकेले 2026 में दर्ज किए गए हैं। विभाग की प्राथमिकता निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करना है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में मादक पदार्थों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया 'ऑपरेशन तूफान' काफी सफल रहा है और इसके लागू होने के बाद आपराधिक मामलों में 35 फीसदी की कमी आई है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।



अब भारत को न्योता देगा पाकिस्तान, एससीओ बैठक में शरीक होंगे जयशंकर?

नई दिल्ली, एजेंसी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बावजूद, दोनों देश एक बार फिर बहुपक्षीय मंच पर संपर्क साधने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत अगले साल की शुरुआत में होने वाली संस्कृति मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है।

यह बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित होगी। भारत इस न्योते पर क्या रुख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एससीओ की पहली सभ्यतागत संवाद बैठक में पाकिस्तान को न्योता दिया था, जिसमें पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भी शामिल हुए थे। अब पाकिस्तान की ओर से भारत को निमंत्रण भेजा जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बैठक में किस स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किसी भी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी ने सितंबर 2025 में



एससीओ के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था।

संस्कृति मंत्रियों की बैठक को राजनीतिक स्तर पर कम संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिबद्धताएं सीमित होंगी, जबकि विदेश या रक्षा मंत्रियों की बैठकें अधिक राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं। संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद, पाकिस्तान एससीओ के विदेश और रक्षा मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठकों के साथ-साथ अगस्त 2026 में राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनका इस्लामाबाद जाना बेहद मुश्किल नजर आता है।

ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और अक्टूबर 2024 में भी वे एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान गए थे (पहलगाम हमले से पहले)। इससे भारत की संगठन के प्रति प्रतिबद्धता भी बनी रहेगी और पाकिस्तान को लेकर उसकी मौजूदा नीति में किसी नरमी का संदेश भी नहीं जाएगा। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भारत- पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नई दिल्ली में मुसादिक मलिक की मेजबानी के बाद भारत ने साफ किया था कि सिंधु जल संधि पर उसका रुख नहीं बदला है। भारत का जोर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ठोस प्रगति पर है और वह ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों के सामान्य होने का संदेश जाए। पाकिस्तान के साथ संबंधों में नरमी की गुंजाइश तभी बन सकती है, जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख में बुनियादी बदलाव दिखाई दे।

पंजाब में शुक्रवार को ब्लैकआउट, रात 8 बजे बजेगा खतरे का सायरन

● राज्य के सभी जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

चंडीगढ़, एजेंसी । पंजाब में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए 27 नवंबर को रात आठ बजे राज्य के सभी जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में प्रशासन और नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को परखना है। अभ्यास की शुरुआत एयर रेड चेतावनी सायरन से होगी। दो मिनट तक ऊंची और धीमी आवाज वाला सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त और नागरिक सुरक्षा नियंत्रक चिन्हित क्षेत्रों में सांकेतिक ब्लैकआउट लागू करेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से गैर-जरूरी रोशनी बंद रखने को कहा गया है। प्रशासन के अनुसार अस्पताल, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी।

यूपी की 11 सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में घमासान

ये वो सीटें हैं जहां सपा खुद को कमजोर मानती है

लखनऊ, एजेंसी । समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध गहरा गया है। सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां सपा संगठनात्मक रूप से खुद को अपेक्षाकृत कमजोर मानती है। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, खासकर अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीटों पर कम हिस्सेदारी को लेकर। सपा के प्रस्ताव में शामिल 20 अतिरिक्त सीटों के क्षेत्रीय बंटवारे पर गौर करें तो, इनमें सबसे अधिक 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। सपा का मानना है कि इन सीटों पर वह अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। ये सभी सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं। इनमें से सात सीटों पर तब राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), जो उस समय सपा गठबंधन का हिस्सा था, दूसरे स्थान पर रही थी। दो सीटों पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) दूसरे स्थान पर रही, जबकि दो सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद दूसरे स्थान पर रही थी। मध्य यूपी की दो प्रस्तावित सीटों में से बिलग्राम-मल्लावां में सपा दूसरे स्थान पर थी, जबकि गोविंद नगर सीट पर उसे 80,896 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वी यूपी की सातों प्रस्तावित सीटों पर भी 2022 में सपा दूसरे स्थान पर रही थी, हालांकि सभी पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इनमें छह सीटें भाजपा ने और एक सीट नानपारा अपना दल (सोनेलाल) ने जीती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर सीट भी इस सूची में शामिल है। सपा के 26 सीटों के प्रस्ताव से कांग्रेस नेताओं में भारी नाराजगी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि अमेठी और रायबरेली जैसी पारंपरिक सीटों पर पार्टी को केवल एक सीट की पेशकश कैसे की जा सकती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 26 सीटों की सूची कैसे दी जा सकती है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया देगी। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हुई एक बैठक में दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। सीटों के बंटवारे पर बातचीत फिलहाल जारी है। कांग्रेस ने पहले 131 सीटों की मांग रखी थी, जिसे घटाकर 120 कर दिया है, जबकि सपा का प्रस्ताव 26 सीटों पर ही अटका है। ऐसे में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनना अभी भी दूर की कौड़ी लग रही है।

एसाईआर में पात्र मतदाताओं के नाम काटने पर भड़के विधायक एमटी राजा, बोले- बांग्ला भाषियों को घुसपैठिया कहना बंद करे विपक्ष

विधानसभा में उधवा और अंबेडकर नगर का मामला उठाया

बिभा संवाददाता



साहेबगंज। झारखंड विधानसभा में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण और घुसपैठ के मुद्दे पर राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बांग्ला भाषी लोगों को घुसपैठिया कहना बंद करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, रिश्तेदारी या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर घुसपैठिया करार देना उचित नहीं है। घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आप लोग बुरी तरह हार चुके हैं और आज सदन के उस पार बैठे हैं। वहीं विधायक ने सदन में एसाईआर प्रक्रिया के दौरान वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जाने की आशंका पर गंभीर चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण जरूरी है, लेकिन इसकी आड़ में वर्षों से मतदान करते आ रहे नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

पुराने बंगाल के दस्तावेजों को लेकर उठाया सवाल

विधायक ने उधवा क्षेत्र के पुराने भू-अभिलेखों और जमीन से संबंधित दस्तावेजों का मामला उठाते हुए कहा कि झारखंड गठन से पहले पुराने दस्तावेजों में नाम, पिता-माता के नाम या वर्तनी की मामूली त्रुटियों के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। इस क्षेत्र के कई लोगों के जमीन संबंधी दस्तावेज पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक सहित अन्य निबंधन कार्यालयों में तैयार हुए थे। उन्होंने तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रेटर बंगाल के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पुराने समय में बिहार, बंगाल और ओडिशा की प्रशासनिक व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई थी। उस दौरान कई सरकारी दस्तावेज बांग्ला भाषा में तैयार किये गये थे। ऐसे में आज की प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर पुराने दस्तावेजों को खारिज करना उचित नहीं है।

अंबेडकर नगर के मतदाताओं का मामला सदन में उठाया

राजमहल प्रखंड के अंबेडकर नगर का मुद्दा उठाते हुए एमटी राजा ने कहा कि वहां वर्षों से रह रहे और लगातार मतदान करते आ रहे कई लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाये जाने की शिकायतें सामने आयी हैं। इनमें ऐसे परिवार भी हैं, जिनके पास जमीन या आवास से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केवल जमीन के कागजात नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति की मतदाता पात्रता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। पूर्व की मतदाता सूची, वोटर आईडी और अन्य स्वीकार्य साक्ष्यों के आधार पर ऐसे लोगों की पात्रता का दोबारा सत्यापन किया जाना चाहिए।

गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों की समस्या पर जतायी चिंता

विधायक ने गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों की परेशानियों को भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि कटाव के कारण कई परिवारों की जमीन और उससे संबंधित दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। ऐसे परिवारों के पास पुराने भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेजों और स्थानीय सत्यापन के माध्यम से उनकी नागरिक एवं मतदाता पात्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उधवा अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

साथ ही विधायक एमटी राजा ने उधवा अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगवाने और अनावश्यक परेशान करने की शिकायतों का जिक्र किया। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

विशेष सहायता केंद्र बनाने की मांग

साथ ही विधायक ने मांग की कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। नाम और वर्तनी में मामूली अंतर को नाम हटाने का आधार नहीं बनाया जाए। पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक साक्ष्य और स्थानीय सत्यापन की व्यवस्था की जाए। साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं, गरीबों और अशिक्षित मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किये जाएं। साथ ही विधायक ने एसआईआर प्रक्रिया के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस प्रक्रिया के बाद आखिर कितने घुसपैठियों की पहचान हुई है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 50 से 55 हजार तक मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात का भी जिक्र किया। विधायक ने सरकार और निर्वाचन तंत्र से एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पूरा करने की मांग की, ताकि कोई भी वास्तविक और पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न हो।

अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, सप्ताह में दो खनन क्षेत्रों की होगी मापी



चेकनाकों का नियमित निरीक्षण, ड्रोन से होगी खनन क्षेत्रों की निगरानी; दोषियों पर होगी कार्रवाई

बिभा संवाददाता

साहेबगंज। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स (खनन) की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग उपस्थित थे। बैठक में जिले में संचालित वैध खनन गतिविधियों की निगरानी के साथ अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो खनन क्षेत्रों की प्रशासनिक मापी कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने जिले के सभी चेकनाकों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने चेकनाकों पर संधारित पंजियों, सीसीटीवी कैमरों, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, वाहनों की संख्या, खनिजों के प्रकार तथा वाहनों के कागजात और चालानों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीसीटीवी कैमरों की नियमित मरम्मत कर उन्हें हमेशा चालू रखने को कहा गया। खनन क्षेत्रों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने अनुमंडल में एक-एक ड्रोन और ऑपरेटर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्रों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी, ताकि अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी अंचल अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों को बालू घाटों का नियमित निरीक्षण करने तथा अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। इसके अलावा अवैध क्रशर, चिमनी, मिट्टी कटाव और बालू से जुड़े मामलों में नियमित जांच एवं प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अवैध खनन पट्टा क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया। उपायुक्त ने अवैध मिट्टी कटाव की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा मामला सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया। वहीं बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, थाना प्रभारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन एवं खनिजों के परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मौके पर जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो, सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

60 टीबी मरीजों को जिला खनन पदाधिकारी ने लिया गोद, बांटी पोषण किट



बरहरवा(बिभा) । झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बुधवार को पतना प्रखंड में पोषण किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने निक्षय मित्र बनकर प्रखंड के इलाजरत सभी 60 टीबी मरीजों को गोद लिया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रहमान ने मरीजों के बीच पोषण किट वितरित की। इस दौरान डॉ. रहमान ने कहा कि टीबी पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है। मरीज नियमित रूप से दवा का सेवन करें और पौष्टिक भोजन लें। वहीं जिला यक्ष्मा विभाग के पीपीएम दिनेश कुमार ने निक्षय मित्र पहल की जानकारी देते हुए समाज के सक्षम लोगों से टीबी मरीजों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की। मौके पर बीपीएम मधुसूदन महतो, देवब्रत कुमार, संजय किस्कू, दीपक टुडू, कृपा सिंधु रजक सहित सभी सहिया एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।

राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा पर विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा



बरहरवा(बिभा) । झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत बुधवार को बरहरवा बीआरसी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड के सरकारी विद्यालयों के कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। केजीबीवी बरहरवा, मध्य विद्यालय रतनपुर, उच्च विद्यालय इस्लामपुर सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने क्विज, निबंध समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रत्येक विद्यालय से दो से तीन विद्यार्थियों ने भाग लिया। मौके पर बीपीओ दीपक कुमार, मोहम्मद अली, बीआरपी शमसुल काबिर सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 परिवारों को मिला पक्का मकान



उधवा(बिभा) । उधवा प्रखंड क्षेत्र में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में ग्रामीण आवास योजना के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे है। इसी क्रम में बुधवार को जोंका एवं सुतियारपाड़ा पंचायत में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों की मौजूदगी में कुल 15 लाभुक परिवारों को उनके नवनिर्मित पक्के मकान में गृह प्रवेश कराया गया। अपने सपनों का आशियाना मिलने पर लाभुकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वर्षों से कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए पक्के घर का सपना पूरा होना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं रहा। गृह प्रवेश के दौरान लाभुकों एवं उनके परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस संबंध में प्रखंड समन्वयक आवास संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पंचायतों में कुल 15 लाभुकों को नवनिर्मित आवास में गृह प्रवेश कराया गया। इनमें जोंका पंचायत के 10 तथा सुतियारपाड़ा पंचायत के पांच लाभुक शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है,ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकें। मौके पर आवास प्रभारी फुल कुमार टोप्पो,विनोद कुमार,संजीव ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बरहरवा में विकास योजनाओं की सौगात, सखी मंडलों को मिले 2.50 करोड़ रुपये

बिभा संवाददाता



बरहरवा। झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत बुधवार को बरहरवा प्रखंड कार्यालय परिसर में परिसंपत्ति वितरण एवं विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। सांसद विजय कुमार हांसदा ने विधिवत दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरूआत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा पारंपरिक लोटा-पानी से अतिथियों के स्वागत, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। अतिथियों को पौधा, शॉल एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में भूमि संरक्षण विभाग की जलनिधि योजना के तहत सात स्थानों पर परकोलेशन टैंक, चेकडैम तथा वीबी-जी राम जी के तहत सड़क, तालाब, बागवानी, रिचार्ज पिट और पशु शेड सहित कुल 15 योजनाएं शिलान्यास के लिए निर्धारित की गईं। वहीं, जेएसएलपीएस की ओर से 90 सखी मंडलों को 1.35 करोड़ रुपये का बैंक क्रेडिट लिंकेज तथा 115 सखी मंडलों को 1.15 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि वितरित की गई। इसके अलावा पांच ग्रामीण और पांच शहरी आवास लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया। 10 लाभुकों को कंबल, सात विद्यार्थियों को साइकिल, एक दिव्यांग को ट्राइसाइकिल, तीन लाभुकों को मनरेगा स्वीकृति पत्र तथा पशुपालन योजना के तहत तीन लाभुकों को 30-30 बतख दिए गए। किसानों के बीच मसूर, सरसों और गेहूं के बीज तथा चार लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वही किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ने के उद्देश्य से जिला उद्यान विभाग द्वारा दो किसान को 'कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई' आवंटित की गई है, जिसकी कुल लागत 3 लाख रुपये है एवं एक किसान को 'फूल एवं फल बिचड़ा उत्पादन इकाई' प्रदान की गई है। इस इकाई की कुल लागत भी 3 लाख रुपये निर्धारित है,जिसमें किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया गया है। साथ ही सांसद ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी अपनी बात रखी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, प्रखंड प्रमुख सुशीला हांसदा, सांसद प्रतिनिधि अब्दुल कादिर, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल गाफुर, बीडीओ सन्नी दास, सीडीपीओ चित्रा यादव, बीपीओ विजय, जैनी किस्कू, कल्याण पदाधिकारी, सीआई सहित अन्य मौजूद थे। वही कार्यक्रम का संचालन जेएसएलपीएस के बीपीएम फैज आलम ने किया।

प्राणपुर में दो दिवसीय वार्षिक जलसा 28 एवं 29 नवंबर को

बिभा संवाददाता



उधवा। उधवा प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण पलाशगाछी पंचायत अंतर्गत प्राणपुर स्थित मदरसा गौसिया फातेमा तुजजहरा बनातुल मुसलेमिन की तामीर एवं तरक्की के उद्देश्य से आगामी 28 एवं 29 नवंबर को दो दिवसीय उर्से गौसे पाक एवं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन किया जाएगा। जलसे को लेकर आयोजन समिति की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर आकर्षक पंडाल भी सजकर तैयार हो गया है। इस संबंध में कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना सौदागर अली ने बताया कि मदरसा के वार्षिक जलसे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मसरूर रजी शहबाजी (भागलपुर) शिरकत करेंगे। वहीं अंतरराष्ट्रीय शायर-ए-इस्लाम शब्बीर बरकाती भी अपनी विशेष प्रस्तुति से जलसे की शोभा बढ़ाएंगे। इसके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह माईनुद्दीन हसन कादरी,मौलाना सुल्तान अहमद सहित क्षेत्र के कई स्थानीय उलेमा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 28 नवंबर को दिन में महिलाओं के लिए विशेष जलसे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्र के लोगों से जलसे में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

विकास योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें : उपायुक्त

बिभा संवाददाता



साहेबगंज। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं, विभिन्न विभागों के कार्यों और लंबित प्रशासनिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में मेडिकल कॉलेज, पावर ग्रिड, साइंस कॉलेज, एकलव्य विद्यालय, नगर परिषद कार्यालय, श्रमिक विद्यालय, श्रमिक चौक, बरहरवा बस स्टैंड, बरहेट में अनाज भंडारण गोदाम, गंगा नदी थाना भवन एवं तीनपहाड़ थाना भवन समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण और भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित भूमि संबंधी मामलों में तेजी लाते हुए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि संबंधी अड़चनों के कारण जनहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। वहीं, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रमाण पत्रों के निष्पादन से जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बीडीओ एवं सीओ को प्रत्येक 15 दिनों में अपने कार्यालय के कर्मियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों और लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा। भू-अर्जन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है, उनके रैयतों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन कर लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करें। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सदर अस्पताल में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत कर निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले की सभी एंबुलेंस का शीघ्र मरम्मतीकरण कराने को कहा, ताकि मरीजों को समय पर आपातकालीन परिवहन सुविधा मिल सके। इसके अलावा जिले के सभी निजी विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन जल्द सौंपने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, राजमहल एसडीओ सदानंद महतो समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

साहेबगंज में नशे के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, स्कूल - कॉलेज के 200 मीटर दायरे में होगी निगरानी

बिभा संवाददाता



साहेबगंज । समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग उपस्थित रहे। बैठक में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खरीद-बिक्री, भंडारण एवं सेवन पर रोक लगाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों को संदिग्ध क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाने तथा नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सीओटीपीए एक्ट का सख्ती से पालन कराने और विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 200 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों व प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखने को कहा। इस क्षेत्र में आने वाले दुकानदारों से शपथ-पत्र भी लिया जाएगा। इसके अलावा जिले के सभी विद्यालयों में नशामुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान, शपथ ग्रहण एवं परिचर्चा आयोजित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।

खेतों की उर्वरता बचाने की पहल, बरहरवा में 105 किसानों को मिला मसूर बीज

बिभा संवाददाता



बरहरवा। खेती की लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने की पहल की है। बुधवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के तत्वावधान में बरहरवा प्रखंड के 105 किसानों के बीच मसूर बीज का वितरण किया गया। इस दौरान किसानों को संदेश दिया गया कि खेतों की सेहत बचाने के लिए डीएपी और यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कम करना जरूरी है। मिट्टी की जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और खेती में वैकल्पिक फसलों को भी अपनाएं। मसूर की खेती को प्रोत्साहित करना इसी प्रयास का हिस्सा है। कृषि कर्मियों ने किसानों से मिट्टी की उर्वरता को प्राथमिकता देते हुए टिकाऊ खेती अपनाने की अपील की। मौके पर बीटीएम अनवारुल अंसारी, एटीएम प्रतिभा कश्यप, हिमांशु महतो सहित अन्य कृषक मित्र मौजूद थे।

संक्षिप्त डायरी

शादी में अंधाधुंध फायरिंग, दो दोस्तों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर; जानिए क्या है मामला

एजेंसी

पटना। बिहार में शादी समारोहों के दौरान सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भोजपुर की इस वारदात ने ग्रामीण इलाकों में बढ़ते आपराधिक दुस्साहस की तस्वीर सामने रखी है। समारोह में अचानक मची चीख-पुकार से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार के भोजपुर जिले में शादी समारोह के दौरान खूनी वारदात सामने आई है। मामा की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे तीन दोस्तों पर हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद शादी की खुशियां चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गईं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीबीगंज चकिया गांव की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को गोलीबारी की वजह माना जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। मृतकों की पहचान शुभकरण गंज गांव निवासी सनोज यादव के 18 वर्षीय बेटे राहुल कुमार और महंत यादव के 22 वर्षीय बेटे दीपक कुमार के रूप में हुई है। वहीं, गोली लगने से दौलतपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव का 18 वर्षीय बेटा सोनू कुमार घायल हुआ है। उसका आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक से शादी समारोह में पहुंचे थे तीनों दोस्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर शाम राहुल कुमार अपने दोस्त दीपक और सोनू के साथ बाइक से बीबीगंज चकिया गांव पहुंचा था। राहुल के मामा रामनरेश यादव की बेटी की शादी थी। तीनों दोस्त समारोह में शामिल थे। इसी दौरान चार-पांच की संख्या में हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और युवकों को निशाना बनाकर गोलियां चलाने लगे। अचानक हुई फायरिंग से समारोह में भगदड़ मच गई। गोली लगने से राहुल और दीपक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि सोनू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे लेकर आरा सदर अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। घायल ने ढेमन यादव और उसके भतीजे पर लगाया आरोप अस्पताल में इलाजरत सोनू कुमार ने पुलिस को बताया कि वह राहुल और दीपक के साथ शादी समारोह में शामिल होने आया था। इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सोनू ने गोलीबारी में ढेमन यादव, उसके भतीजे आशीष यादव और तीन-चार अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। घायल का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह केवल शादी में शामिल होने आया था। सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि 24 और 25 नवंबर की मध्यरात्रि करीब 11 बजे चकिया गांव में शादी समारोह के पास गोलीबारी हुई थी। इसमें तीन युवकों को गोली लगी थी। इलाज के दौरान राहुल और दीपक की मौत हो गई, जबकि सोनू घायल है। शुरूआती जांच में पुराना विवाद सामने आया है। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है। घटनास्थल से तीन खोखे और एक पिलेट बरामद किए गए हैं। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।

बिहार का सबसे चर्चित इवेंट शुरू; शिवांगी की शादी में क्या-क्या अलग होगा

एजेंसी

पटना। बाहुबली विधायक आनंद सिंह की बेटी शिवांगी की शादी आज है। 151 गाड़ियों का काफिला बारात में होगा। शादी से पहले उपहारों की बारिश भी होगी। जानें, हर अपडेट। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश सिंह से आज होने वाली है। इसके लिए बाढ़ के नदवां गांव स्थित अनंत सिंह के पैतृक आवास पर भव्य तैयारियां की गई हैं। करीब 10 बीघा जमीन में पंडाल तैयार किया गया है। चार लाख लोगों के खाने-पीने का इंतजाम किया गया है। मेहमानों को 140 से अधिक व्यंजन परोसे जाएंगे। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से पंडाल बनाए गए हैं। यहां 30 स्टॉल लगाए गए हैं। तीन दिन पहले से ही 500 से अधिक हलवाई भोजन तैयार करने में जुटे हैं। सुबह 10 बजे से भोज शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि शादी समारोह शुरू होने से पहले घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता दोपहर दो बजे होगी। जीतने वाले घुड़सवार को बाहुबली अनंत सिंह खुद सफेद रंग की महिंद्रा थार गाड़ी उपहार में देंगे। प्रतियोगिता में बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी घुड़सवार पहुंचे हैं। दूल्हा ऋषिकेश सिंह 151 गाड़ियों के काफिले के साथ बारात लेकर नदवां पहुंचेंगे घुड़दौड़ प्रतियोगिता के समापन के बाद सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारियों में जुट जाएंगे। बारात पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर से आएगी। रात आठ बजे तक दूल्हा ऋषिकेश सिंह 151 गाड़ियों के काफिले के साथ बारात लेकर नदवां पहुंचेंगे। बारातियों का स्वागत भी खास अंदाज में किया जाएगा। रात नौ बजे वरमाला का कार्यक्रम निर्धारित है। वरमाला का मंच जयपुर की थीम पर तैयार किया जा रहा है। जयमाला मंच के सामने मैदान में रेस्टोरेंट की तर्ज पर विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं, अनंत सिंह खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। वरमाला के बाद विवाह की रस्में शुरू होंगी। इस दौरान बारातियों और अन्य मेहमानों के भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। बारातियों के लिए विशेष व्यंजनों का इंतजाम किया गया है। शादी समारोह में बिहार के नामी कलाकार शामिल होंगे। अनंत सिंह ने पहले ही कहा था कि शादी में बिहार के ही नहीं बाहर के राज्यों के भी लोग आएंगे। उन्होंने सियासी गलियारे के सभी बड़े नामों को न्यौता भेजा है। तिलकोत्सम में भी कई मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हुए थे। आज भी कई बड़े दिग्गज कार्यक्रम में आएंगे। इसके अलावा फिल्म अभिनेता सोनू सूद, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, गायक गुंजन सिंह के अलावा कई सेलिब्रेटी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शादी समारोह में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश और निकास के रास्ते अलग-अलग बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इलाके में जाम की समस्या न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मोर्चा संभालेंगे। वहीं, तीन हजार से अधिक निजी बाउंसर मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेलीपैड स्थल पर भी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

फतुहा मुठभेड़ कांड में जब्त वाहनों से फिर मिले 102 कारतूस और देसी पिस्टल, यूपी से कौन सा तार जुड़ा

एजेंसी

पटना। फतुहा मुठभेड़ मामले की जांच में एसटीएफ को एक और अहम सुराग मिला है। पहले जब्त किए गए वाहनों की दोबारा जांच में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी को कारतूस की आपूर्ति के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आइये जानते हैं पूरा मामला... पटना जिले के फतुहा में हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में बिहार एसटीएफ ने जब्त वाहनों की दोबारा तलाशी लेकर हथियारों और कारतूस की एक और खेप बरामद की है। दोनों वाहनों से 315 बोर के 102 जिंदा कारतूस और 32 बोर की एक देसी पिस्टल मिली है। अदालत के आदेश पर 23 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फतुहा थाना परिसर में तलाशी की कार्रवाई की गई। मामला 11 मार्च 2026 का है। उस दिन फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें पटना निवासी शत्रुघ्न कुमार और सारण जिले के सुजीत कुमार व सुंदरम कुमार शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपितों के कब्जे से दो वाहनों में रखे कुल 1170 कारतूस बरामद किए गए थे। मोबाइल की जांच में मिला उत्तर प्रदेश से सप्लाई का सुराग मामले की जांच के दौरान बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने आरोपितों के मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया। इसके आधार पर कारतूस की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई गई। जांच में उत्तर प्रदेश से कारतूस की सप्लाई होने का सुराग मिला। इसी दौरान एसटीएफ को आशंका हुई कि पहले जब्त किए गए दोनों वाहनों में कुछ और कारतूस छिपाकर रखे गए हो सकते हैं। इसके बाद टीम ने अदालत से वाहनों की दोबारा तलाशी लेने की अनुमति मांगी।

2027 तक बनेगा एआई और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, 200 युवाओं को मिलेगा

एजेंसी

पटना। बिहार में 2027 तक अक और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में सूचना प्रावैधिकी विभाग और टाइगर एनालिटिक्स के बीच एमओयू हुआ। इस परियोजना से करीब 200 युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की तैयारी है। राज्य में वर्ष 2027 तक अकएवं मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से करीब



200 युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी विभाग और अककंपनी टाइगर एनालिटिक्स इंडिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पटना स्थित लोक सेवक आवास के 'संकल्प' सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस समझौते पर सहमति बनी। परियोजना के तहत टाइगर एनालिटिक्स इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभाएगा। सरकार का उद्देश्य इस सेंटर के माध्यम से बिहार को देश के प्रमुख AI इकोसिस्टम हब के रूप में विकसित करना है। इस ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के माध्यम से राज्य के छात्र-छात्राओं, युवाओं, तकनीकी पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं की तकनीकी दक्षता और कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस पहल से युवाओं को भविष्य की उभरती तकनीकों के अनुरूप रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य में तकनीकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तीन नीतियों के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी बिहार सरकार राज्य में तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने नीतियों के तहत कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीकी आधारभूत संरचना और कारोबार स्थापित करने में सुगमता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि AI और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की स्थापना से बिहार के आईटी और AI इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी सह नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और टाइगर एनालिटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट एवं ग्लोबल हेड बद्रीश प्रकाश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आधी रात घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, 20 मीटर दूर ले जाकर माथे में मारी गोली

एजेंसी

पटना। खगड़िया के दोघराहा गांव में बुधवार रात चार लड़के 26 वर्षीय सोनू सदा को घर से बुलाकर ले गए और 20-25 मीटर दूर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली माथे से आर-पार हो गई। पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच कर रही है। बिहार के खगड़िया जिले में अपराधियों ने घर से बुलाकर 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बुधवार देर रात गंगौर थाना क्षेत्र की वरैय पंचायत के दोघराहा गांव में हुई। अपराधियों ने युवक को घर से करीब 20 से 25 मीटर दूर ले जाकर माथे में गोली मार दी। गोली आर-पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 14 निवासी सोनू कुमार उर्फ सोनू सदा (26) के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। रात 1:30 बजे घर पहुंचे थे चार लड़के मृतक की मां ममता देवी ने बताया कि बुधवार रात करीब 1:30 बजे चार लड़के उनके घर पहुंचे थे। सभी सोनू को घर से बुलाकर बाहर ले गए। इसके बाद घर से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर उसे गोली मार दी। गोली सोनू के माथे में लगी और आर-पार हो गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सोनू के पिता का नाम सोगारत सदा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोग मौके पर जुट गए। परिवार में भी मातम पसर गया। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य वारदात की सूचना मिलने पर गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान और सदर डीएसपी-2 संतोष कुमार पोद्दार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सदर डीएसपी-2 संतोष कुमार पोद्दार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, खगड़िया भेज दिया है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

अख्तरुल ईमान के बयान पर महिला आयोग सख्त, सात दिन में मांगा जवाब; कार्रवाई की चेतावनी

एजेंसी

पटना। महिलाओं और विवाह समारोहों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने सात दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। विवाह समारोहों और महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं अमौर विधायक अख्तरूल ईमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने विधायक से सात दिनों के भीतर लिखित जवाब



मांगा है। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य सजल झा ने 24 नवंबर 2026 को यह नोटिस जारी किया। इसमें सार्वजनिक मंच से अमर्यादित, भड़काऊ और विवादास्पद बयान देने के मामले में विधायक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आयोग ने वीडियो का लिया संज्ञान, बताया सार्वजनिक मयार्दा के विरुद्ध आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उसके संज्ञान में अख्तरूल ईमान का एक वीडियो आया है। इसमें वह सार्वजनिक मंच से महिलाओं और विवाह समारोहों को लेकर कथित तौर पर अभद्र एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अन्य संवैधानिक मुद्दों पर भी भड़काऊ बयान देने का उल्लेख किया गया है। आयोग ने इस तरह की टिप्पणी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और सार्वजनिक मयार्दा के विरुद्ध बताया है। विधायक को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, अख्तरूल ईमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह मुस्लिम समाज में विवाह के दौरान होने वाली रस्मों, दुल्हन की मुंह दिखाई, वलीमा में उपहार लेने और शादी में होने वाली फिजूलखर्ची को लेकर टिप्पणी करते नजर आए थे। इसी दौरान दुल्हन की नुमाइश की तुलना तवायफ से करने वाली उनकी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बयान की आलोचना की थी। अब बिहार राज्य महिला आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला नए सिरे से चर्चा में है। आयोग ने विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया है। फिलहाल अख्तरूल ईमान की ओर से नोटिस के जवाब में क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर नजरें टिकी हैं।

बिहार में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: एक युवक की मौत; मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों समेत चार घायल

एजेंसी

पटना। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 25 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। हादसे में मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल को पटना रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक निजी मेडिकल कॉलेज के दो छात्र भी शामिल हैं। हादसा तुर्की थाना क्षेत्र के तुर्की-छाजन रोड पर रात के समय हुआ। घायलों में एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जुट गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार, तीन युवक तुर्की चौक स्थित मछली की दुकान से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज के दो छात्र दूसरी बाइक से तुर्की की ओर जा रहे थे। तुर्की-छाजन रोड पर दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार सभी पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में छाजन मनरिया निवासी करीब 25 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पंकज कुमार और महेश सहनी समेत चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ वेस्ट-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में कुल पांच युवक घायल हुए थे। इनमें दो मेडिकल कॉलेज के छात्र और तीन स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हैं। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर, इस दुर्घटना में राकेश कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

हरजोत कौर बम्हरा बनीं बीपीएससी की नई अध्यक्ष, 29 नवंबर से संभालेंगी जिम्मेदारी

एजेंसी

पटना। बिहार सरकार ने 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को इढरउ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 29 नवंबर 2026 से पदभार संभालेंगी। इससे एक दिन पहले उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उनका कार्यकाल छह साल या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा। बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, उनकी नियुक्ति 29 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। इससे एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हरजोत कौर बम्हरा 1992 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी हैं। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत उन्हें इढरउ अध्यक्ष नियुक्त



किया है। सरकार ने इस संबंध में दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहली अधिसूचना में 28 नवंबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और दूसरी में 29 नवंबर से आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का आदेश दिया गया है। छह साल या 62 वर्ष की उम्र तक संभालेंगी पद सरकारी अधिसूचना में उनके कार्यकाल की अवधि भी स्पष्ट की गई है। संविधान के अनुच्छेद 316(2) के प्रावधानों के अनुसार, हरजोत कौर बम्हरा पदभार ग्रहण करने की तारीख से छह साल या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक इढरउ की अध्यक्ष रहेंगी। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त होगा। इढरउ की भर्ती प्रक्रियाओं और नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे समय में हरजोत कौर बम्हरा को आयोग की कमान सौंपना अहम माना जा रहा है। उनकी पहचान बिहार में एक सख्त और अनुशासनप्रिय अधिकारी के रूप में रही है। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी।

अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी, घुड़दौड़ के लिए तैयार हुआ मैदान, मेहमानों के लिए बन रहे दो हेलिपैड

एजेंसी

पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी आज हो रही है। समारोह में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। मैदान में पानी भरने के बाद ट्रैक्टर, बालू और रोड रोलर की मदद से रेस ट्रैक तैयार किया गया है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी आज धूमधाम से होने जा रही है। शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। इसके लिए मैदान को तैयार करने में अनंत सिंह खुद जुटे हुए हैं। मंगलवार देर रात करीब एक बजे तक वह मैदान में मौजूद रहकर तैयारियों का जायजा लेते



रहे। बुधवार सुबह करीब नौ बजे भी वह दोबारा मैदान पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों और लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं, आने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए दो हेलिपैड बनाए जा रहे हैं। एक हेलिपैड देर रात तक तैयार कर लिया गया था, जबकि दूसरा बनाने के लिए बुधवार सुबह से ही दर्जनों मजदूर काम में जुटे हैं। अनंत सिंह के बेटे भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पानी भरने से बिगड़ी थी मैदान की स्थिति, ट्रैक्टर और रोड रोलर से बदली तस्वीर शादी समारोह में घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर मैदान में विशेष तैयारी की गई है। हाल ही में मैदान में पानी जमा हो जाने के कारण प्रतियोगिता के आयोजन पर संशय पैदा हो गया था। इसके बाद अनंत सिंह ने समर्थकों के साथ मैदान को तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली। मैदान को समतल करने के लिए कई ट्रैक्टर लगाए गए। इसके बाद रेत और बालू बिछाई गई और रोड रोलर चलाकर रेस ट्रैक को बेहतर बनाया गया। रातभर चले काम के बाद अब मैदान घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया है। सुबह से ही घोड़ों को मैदान में दौड़ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। बिहार, यूपी और पंजाब के घोड़े दिखाएंगे रफ्तार का दम मोकामा में होने वाली इस प्रतियोगिता में बिहार के अलग-अलग जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी घोड़े पहुंचे हैं। मैदान में कई घोड़े लगातार अभ्यास कर रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर घोड़ा मालिकों और आयोजकों में उत्साह है। इसमें समस्तीपुर से पहुंचे डोमन मुखिया का घोड़ा राजा भी चर्चा में है। अनंत सिंह के करीबी डोमन मुखिया का घोड़ा राजा पिछली बार नदवा में आयोजित रेस का विजेता रहा था। भारत केसरी के नाम से मशहूर राजा राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार जीत चुका है। डोमन मुखिया के मुताबिक, राजा जिस प्रतियोगिता में उतरता है, उसमें जीत हासिल करता है। इसी वजह से अब वह राजा को घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में नहीं उतारते हैं। उसकी अगली पीढ़ी रेस में उतरने के लिए तैयार है। शादी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर अनंत सिंह लगातार सक्रिय हैं। मैदान में पानी जमा होने के बाद आयोजन को लेकर जो आशंका थी, उसे दूर करने के लिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। देर रात तक मैदान में काम चलता रहा। सुबह होते ही घोड़ों की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैदान तैयार होने के बाद आयोजन से जुड़े लोगों और घोड़ा मालिकों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है।

लातेहार के मंगरा गांव पहुंचे सीएम हेमन्त सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन, वर-वधू को दिया आशीर्वाद

बिभा संवाददाता





लातेहारः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी-सह-विधायक कल्पना सोरेन के साथ आज लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित मंगरा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचन्द्र सिंह के सुपुत्र चि० विजय बहादुर सिंह के शुभ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। इस मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने विजय बहादुर एवं आयु० कुमारी महिमा (नवदंपती वर-वधू) को स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके नवजीवन की सुखद शुरूआत की मंगलकामना की। साथ ही नवदंपती के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव और खुशहाली सदैव बनी रहे, इसकी कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने विधायक तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों एवं सगे-संबंधियों से आत्मीय मुलाकात कर खुशी जाहिर की और परिवारजनों को भी इस मांगलिक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं स्थानीय आम नागरिकों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को मंगरा गांव पहुंचने पर हैलिपैड पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर किया गया तथा स्वागत किया गया। मौके पर प्रमण्डलीय आयुक्त कुमूद सहाय, पलामू क्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल, लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव,उप विकास आयुक्त लातेहार सैय्यद रियाज अहमद आदि पदाधिकारीगण, स्थानीय जन प्रतिनिधिगण एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

राष्ट्र रक्षा यज्ञ से सामाजिक एकता और समरसता को मिलेगी मजबूती : अनिल गुप्ता



रघु टोली महावीर मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ राष्ट्र रक्षा यज्ञ, सामूहिक आरती कर की गई राष्ट्र की सुख-समृद्धि की कामना

बिभा संवाददाता

लोहरदगा। समाज में एकता, समरसता, सांस्कृतिक चेतना तथा सनातन संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के तत्वावधान में रघु टोली स्थित महावीर मंदिर परिसर में राष्ट्र रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। धार्मिक वातावरण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधानपूर्वक यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ के उपरांत सामूहिक आरती कर राष्ट्र की सुख-समृद्धि, शांति, उन्नति और सामाजिक एकता की कामना की गई। यज्ञ अनुष्ठान सुशांत पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी गोपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, आपसी सहयोग बढ़ाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है और लोगों में अपनी संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने कहा कि वन एवं नगरीय वंचित समाज के उत्थान को समर्पित ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ना तथा प्रत्येक परिवार में सनातन संस्कारों को मजबूत करना है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से ही संगठित, संस्कारित और समरस समाज का निर्माण संभव है। समाजसेवी चंदन गोप ने कहा कि सनातन संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। माताओं, बहनों और बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक दिन मंदिर जाकर हवन, पूजा-पाठ एवं धार्मिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। वहीं, समाजसेवी चमन गोप ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार विकसित होते हैं तथा परिवार और समाज में धार्मिक चेतना एवं एकता की भावना मजबूत होती है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग और समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जागेश्वर गोप, रंजन गोप, सचिन कुमार, धनंजय अग्रवाल, सोनू गोप, दीपक कुमार, कुंदन गोप, राहुल कुमार, मनीष गुप्ता, सविता उरांव, लक्ष्मी उरांव, सुखमणि उरांव, देवंती भगत, आशा कुमारी, संगीता देवी, रजनी उरांव, मुन्नी देवी सहित बड़ी संख्या में रामभक्त, माताएं, बहनें एवं फाउंडेशन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

स्वामी धर्म बंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पुस्तक दान शिविर का आयोजन



हजारीबाग(बिभा) : स्वामी धर्मबंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पुस्तक दान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. सारिका कुमारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्या डॉ. सारिका कुमारी ने महाविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए 66 पुस्तकें दान कीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें ज्ञान का अमूल्य भंडार होती हैं। पुस्तक दान करना केवल पुस्तकों का दान करना नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और विचारों का प्रसार करना है। इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि विकसित होती है तथा पुस्तकालय को समृद्ध बनाने में सहयोग मिलता है। उन्होंने सभी से पुस्तक दान जैसे पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी सहायक प्राध्यापकगण, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं बी.एड. सत्र 2026-28 के सभी शिक्षक प्रशिक्षु उपस्थित रहे।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुस्तक दान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुस्तकालय को समृद्ध बनाना तथा विद्यार्थियों में अध्ययन एवं पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना था।

घाघरा में जनजातीय गौरव दिवस समारोहः आयोग को मिले 83 आवेदन, जमीन व मूलभूत सुविधाओं की मांग प्रमुख



घाघरा (गुमला)(बिभा): गुमला के घाघरा प्रखंड स्थित एस.एस. +2 उच्च विद्यालय मैदान में 23 नवंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्वावधान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गुमला और लोहरदगा जिलों के विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं व मांगों से जुड़े कुल 83 आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। शिकायतों में जमीन पर अवैध कब्जा, खतियान में गड़बड़ी, अवैध पत्थर उत्खनन व क्रेशर संचालन, आवास योजना, सड़क व पुल निर्माण, सिंचाई व पेयजल सुविधा, राशन कार्ड, जाति-आवासीय प्रमाण पत्र, रोजगार, शिक्षा तथा पुलिस व प्रशासनिक मामलों से जुड़े विषय शामिल रहे। आयोग ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सभी आवेदनों को विषय और विभाग के आधार पर संकलित किया। आयोग के अनुसार, नियमानुसार परीक्षण के बाद इन मामलों को संबंधित विभागों और सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा।

धनबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल, वायरलेस सेवा के 23 पुलिसकर्मियों का तबादला

धनबाद(बिभा)। झारखंड पुलिस वायरलेस सेवा से जुड़े साक्षर पुलिसकर्मियों का राज्य स्तर पर स्थानांतरण किया गया है। इनमें वे कर्मी शामिल हैं, जो लंबे समय से एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापित थे। धनबाद जिले के 23 पुलिसकर्मियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। पुलिस वायरलेस मुख्यालय, झारखंड ने सभी को तत्काल नए स्थान पर योगदान देने का आदेश दिया है। स्थानांतरित कर्मियों में तोपचांची थाना के विशाल कुमार तिवारी, लोयाबाद के निर्मल कुमार महतो, कतरास के राजा कुमार, एचएफ-वीएचएफ धनबाद के सौरभ कुमार, रवि कुमार, बबलू कुमार रवानी, अमृत हेम्ब्रम और नंदकिशोर साव शामिल हैं। इनके अलावा बरवाअड्डा के महेश प्रसाद महतो, सिंदरी के बागेश्वर बाउरी, धनसार के अमीन किस्कू, पाथरडीह के अशोक कुमार हांसदा, महुदा के बैद्यनाथ रजवार और पूर्वी टुंडी के शंकर मोदी का भी स्थानांतरण हुआ है। नगर थाना की पिंकी महतो और नीलम कुमारी, केंदुआडीह की अशांका कुमारी, महिला थाना की चांदनी कुमारी, सरायढेला की प्रीति कुमारी, निरसा की आशा कुमारी, बैंक मोड़ की सुमनी कुमारी तथा सीसीटीएनएस धनबाद के सद्दाम अंसारी और प्रीति कुमारी भी इस सूची में हैं। सभी को रांची, लातेहार, खूंटी, आइआइ कंट्रोल, चाइल्ड थाना समेत अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया गया है।

होटल उपकार में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, एक की मौत, एक घायल

बिभा संवाददाता



हजारीबाग : हजारीबाग में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब शहर के उपकार होटल में शादी समारोह के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। द्वारपूजा की रस्म के बीच हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान हुरहुरू स्थित बाबा पथ निवासी अर्णव सिंह उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। वहीं, घायल अंकित कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की रात उपकार होटल में शादी समारोह के साथ संगीत कार्यक्रम आयोजित था। बारात चतरा जिले के सिमरिया से आई थी। इसी दौरान द्वारपूजा की रस्म के समय बाराती और सराती पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और फिर अचानक गोलियां चलने लगीं। गोलीबारी में अर्णव सिंह और अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अर्णव ने दम तोड़ दिया। घटना में गोली चलाने का आरोप बारातियों पर लगाया जा रहा है। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां बार-बार बेसुध हो रही हैं। परिवार के लोगों के लिए शादी की खुशियों के बीच आई यह त्रासदी असहनीय बन गई है।

मृतक के भाई विक्रम ने बताया कि उनके घर के समीप ही शादी समारोह आयोजित था और परिवार को निमंत्रण मिला था। इसी निमंत्रण पर उनका भाई अर्णव होटल पहुंचा था। वहां अचानक विवाद हुआ और उनके भाई को गोली मार दी गई। उन्होंने घटना में शामिल दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बड़कागांव से 28 नवंबर को रवाना होगा सांसद तीर्थ दर्शन महाभियान का 100वां और 101वां जत्था



बिभा संवाददाता

हजारीबाग : हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल की ओर से संचालित सांसद तीर्थ दर्शन महाभियान का 100वां और 101वां जत्था आगामी 28 नवंबर को बड़कागांव से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। इस अवसर पर सांढ़ और नयाटांड़ पंचायत के 130 बुजुर्ग श्रद्धालु काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम के दर्शन करेंगे।

इस ऐतिहासिक पड़ाव पर बड़कागांव थाना के सामने स्थित मां अम्बे परिसर, गुरुचट्टी में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरूआत हवन-पूजन से होगी। इसके बाद बुजुर्ग श्रद्धालुओं के पांव पखारकर और पुष्पवर्षा कर सम्मानपूर्वक विदाई दी जाएगी। सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में तीर्थयात्री बड़कागांव चौक से करीब दो किलोमीटर की पदयात्रा कर सूर्य मंदिर पहुंचेंगे, जहां से यात्रा रवाना होगी। पदयात्रा में संकीर्तन टोली, टाना भगत, शंखनाद, छऊ नृत्य और ताशा पार्टी विशेष आकर्षण होंगे। इधर, सांसद मनीष जायसवाल ने सदर विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आयोजन को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। आयोजन में क्षेत्र की सभी 83 पंचायतों से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है।

मौके पर सांसद प्रतिनिधि अजय साहू, किशोरी राणा, रंजन चौधरी, जीवन मेहता, दामोदर प्रसाद, बलदेव बाबू, कृष्णा मेहता, बीरेंद्र कुमार बीरू, लब्बू गुप्ता, मिथलेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहें ।

छठ महापर्व के सफल आयोजन पर नगर निगम ने कर्मियों को किया सम्मानित, पत्रकारों को भी मिला सम्मान

बिभा संवाददाता



हजारीबाग : छठ महापर्व के सफल, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले नगर निगम के सफाईकर्मियों, बिजली विभाग के कर्मियों एवं निगम के सभी कर्मचारियों के सम्मान में बुधवार को निर्मल महतो पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मंच संचालन सहायक नगर आयुक्त अनिल पांडे ने किया। मौके पर नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता, महापौर अरविंद राणा, उपमहापौर अविनाश यादव सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान छठ महापर्व के आयोजन को सफल बनाने में दिन-रात जुटे कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके समर्पित सेवा कार्यों की सराहना की गई। घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सुविधाओं के प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं में कर्मियों के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। नगर निगम की ओर से पत्रकारों को भी फूलों का गुलदस्ता देकर पर्व के दौरान उनके समाचार एवं जनहित में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा कि छठ महापर्व जैसे बड़े आयोजन को सफल बनाना सामूहिक प्रयास का परिणाम है। नगर निगम के कर्मियों ने पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सभी कर्मियों की मेहनत और सहयोग से शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी। उन्होंने कहा कि कर्मियों का सम्मान उनके उत्साह को बढ़ाने के साथ भविष्य में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। साथियों उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से नए साल तक शहर को स्वच्छता का महोत्सव को धरातल पर लाकर लोगों को एक संदेश दे कि किस तरह शहर को स्वच्छ सुंदर और विकसित कर सके। उन्होंने कहा की कलम की ताकत जितनी प्रखर होती है उतने ही झाड़ू की भी ताकत और नहीं सहनशीलता के साथ प्रखर होती है। महापौर अरविंद राणा ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान नगर निगम के कर्मियों ने सेवा भावना के साथ काम करते हुए शहरवासियों और व्रतियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान भी नगर निगम कर्मियों की सेवा को सम्मानित किया गया था और आज छठ महापर्व के दौरान उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए पुनः सम्मान किया जा रहा है। कर्मियों की मेहनत, समर्पण और जिम्मेदारी शहर के हर बड़े आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने सभी कर्मियों के प्रति आभार जताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उपमहापौर अविनाश यादव ने कहा कि पर्व के दौरान सफाई, बिजली एवं अन्य व्यवस्थाओं में जुटे सभी कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा। नगर निगम की पूरी टीम ने एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाई, जिसका परिणाम सफल आयोजन के रूप में सामने आया। उन्होंने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा की। समारोह के अंत में सभी कर्मियों एवं पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और उनके योगदान को शहर की बेहतर व्यवस्था एवं सफल छठ आयोजन का महत्वपूर्ण आधार बताया गया।

लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद, रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में रेड आर्मी गुमला ने मारी बाजी

खेल को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, खिलाड़ियों की प्रतिभा और खेल भावना का करें सम्मान : धीरज प्रसाद साहू

बिभा संवाददाता



लोहरदगा/गुमला। गुमला स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित द्वितीय लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला राजा क्लब बरयातो एवं रेड आर्मी गुमला के बीच खेला गया। रोमांच और संघर्ष से भरे इस मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अंततः पेनाल्टी शूटआउट में रेड आर्मी गुमला की टीम ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया।

फाइनल समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजन समिति एवं खेल प्रेमियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि धीरज प्रसाद साहू सहित मंचासीन अतिथियों ने परमवीर अल्बर्ट एक्का के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद श्री साहू ने मैदान में पहुंचकर फाइनल मुकाबले में शामिल दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। तत्पश्चात मंच पर मुख्य अतिथि धीरज प्रसाद साहू सहित सभी विशिष्ट अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर श्री साहू ने विजेता रेड आर्मी गुमला एवं उपविजेता राजा क्लब बरयातो की टीम को मोमेंटो और चेक प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि खेल समाज को जोड़ने, आपसी भाईचारे को मजबूत करने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम है। खेल को खेल की भावना से ही देखा जाना चाहिए, इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। खेल किसी राजनीतिक दल, जाति या धर्म का नहीं होता, बल्कि यह सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। खेल के मैदान में राजनीति करना खिलाड़ियों के उत्साह और खेल भावना को प्रभावित करता है। इसलिए सभी को खेल और खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुमला वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का की धरती है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। खेल प्रतियोगिता के माध्यम से उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने का आयोजन समिति का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। श्री साहू ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। विशेषकर गुमला के युवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। आवश्यकता है कि उन्हें उचित अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन मिले। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष और भव्य रूप लेगी तथा यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश-दुनिया में गुमला और झारखंड का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि निशिथ जायसवाल, मिसिर कुजूर, निश्चय वर्मा, दीपांकर साहू, रोहित भगत, अमित वर्मा सहित आयोजन समिति के सदस्य, गणमान्य अतिथि एवं हजारों की संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

आईआईटीएफ के अंतिम दिनों में भी दर्शकों को लुभा रहा झारखंड पवेलियन, माटी कला का लाइव डेमो आकर्षण का केंद्र

बिभा संवाददाता

नई दिल्ली/रांचीः भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आईटीएफ)-2026 में झारखंड पवेलियन में माटी कला बोर्ड की ओर से मिट्टी के बर्तन बनाने की लाइव डेमो प्रस्तुति लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। चाक पर मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक तकनीक से सुंदर कलाकृतियां तैयार करते कारीगरों को देखकर दर्शक इस कला को करीब से जानने व समझने में रुचि ले रहे हैं।



इस दौरान हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग की निदेशक प्रीति रानी ने भी लाइव डेमो प्रस्तुति में भाग लिया और स्वयं चाक पर मिट्टी को आकार देकर झारखंड की पारंपरिक माटी कला का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की मिट्टी में यहां की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता की अनूठी पहचान समाहित है। माटी कला केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक आजीविका का अहम हिस्सा है। ऐसे लाइव डेमो से लोगों को स्थानीय कलाकारों की मेहनत और हुनर को नजदीक से जानने का मौका मिलता है।

चयनित उत्पादों पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट

मेले के समापन के करीब पहुंचने के साथ झारखंड पवेलियन के विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। कई स्टॉलों पर चयनित उत्पादों की खरीद पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है, जिससे आगंतुक पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक वस्तुओं की खरीदारी आकर्षक दामों पर कर सकते हैं। कला, संस्कृति, पारंपरिक हुनर और किफायती खरीदारी का यह संगम मेले के अंतिम दिनों में भी दर्शकों को खूब लुभा रहा है।

उपायुक्त ने रामरेखा धाम की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समेटे स्मारिका का किया विमोचन



बिभा संवाददाता

सिमडेगा। द्वितीय राजकीय रामरेखा महोत्सवञ्ज2026 के अवसर पर रामरेखा धाम की धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं पर्यटन संबंधी विरासत को समेटे स्मारिका का विमोचन मंगलवार को समाहरणालय सभागार में किया गया। उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह, उप विकास आयुक्त श्री दीपांकर चौधरी, अपर समाहर्ता श्री गिरिजा शंकर महतो, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्रीमती सरोज तिर्की एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता श्रीमती अरुणा कुमारी ने संयुक्त रूप से स्मारिका का विमोचन किया।

स्मारिका में रामरेखा धाम की धार्मिक मान्यताओं, भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़ी प्रचलित कथाओं, बीरू राजघराने के इतिहास, स्वर्गीय आचार्य रमापति की साहित्यिक रचना रामरेखा महात्म्य तथा धाम के प्रमुख धार्मिक स्थलों का विस्तृत परिचय दिया गया है। साथ ही सिमडेगा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और रामरेखा धाम में हो रहे विकास कार्यों को भी स्थान दिया गया है।

स्मारिका का विशेष आकर्षण उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह द्वारा रचित ह्यश्रीरामरेखा धाम स्तुतिह्ण है, जिसमें गीतात्मक शैली में धाम की महिमा एवं प्रभु श्रीराम के आदर्शों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह ने कहा कि रामरेखा धाम सिमडेगा की धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्मारिका के माध्यम से इस गौरवशाली विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा जिले की पर्यटन संभावनाओं को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है।

यह स्मारिका रामरेखा धाम की आस्था, इतिहास, साहित्य और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी।

संक्षिप्त खबरें

धनबाद पुलिस का रिकॉर्ड रूम हुआ आधुनिक, 19 रैक में सुरक्षित रहेंगी 1.10 लाख फाइलें



धनबाद(बिभा)। धनबाद पुलिस ने पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सुरक्षित संधारण तथा रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है। समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय में तैयार आधुनिक रिकॉर्ड रूम का बुधवार को बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आधुनिक रिकॉर्ड रूम में कुल 19 रैक बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1.10 लाख फाइलें सुरक्षित रखी जा सकेंगी। फाइलों की पहचान और खोज आसान बनाने के लिए इंडेक्सिंग, लेबलिंग और निर्धारित क्रम की व्यवस्था की गई है। इससे पुराने मामलों से जुड़े दस्तावेज जरूरत पड़ने पर कम समय में उपलब्ध हो सकेंगे। इस रिकॉर्ड रूम की खासियत जापानी 5एस लीन मैनेजमेंट तकनीक है। इसके तहत अनावश्यक दस्तावेजों को अलग करना, फाइलों को निर्धारित क्रम में रखना, नियमित साफ-सफाई, एक समान रखरखाव प्रक्रिया और व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के सिद्धांत अपनाए गए हैं।

दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण भी लगाए गए हैं। इनके रखरखाव के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उद्घाटन के बाद आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पुलिस अभिलेखों का प्रबंधन अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित होगा। पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के साथ जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे पुलिस के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। उन्होंने इसे पूरे झारखंड के लिए प्रेरणादायी पहल बताया।

स्थापना दिवस पर धनबाद के पांच लाभुकों को ट्रैक्टर और आठ महिला उद्यमियों को सम्मान



धनबाद(बिभा)। झारखंड स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियां, चेक, कृषि उपकरण और नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। समारोह का खास आकर्षण मंईयां सम्मान योजना से स्वरोजगार शुरू करने वाली जिले की आठ महिला उद्यमियों का सम्मान रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन बोकारो रेंज के आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मानित महिलाओं में मौसमी सिन्हा (कपड़ा दुकान), रूबी घोष (बताशा फैक्ट्री), मीना रवानी (पलाश दीदी कैफे), रानी दत्ता (राशन दुकान), गुड़िया कुमार (ब्यूटी पार्लर), नेहा देवी (जूट बैग उत्पादन), बबीता कुमारी (हैचरी) और शोभा गोराई (सिलाई सेंटर) शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना की सहायता से महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। किसानों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत पांच ट्रैक्टर और कृषि यंत्र दिए गए। किसान समृद्धि योजना के तहत पांच लाभुकों को सोलर पंप, 21 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और 20 को बीज वितरित किए गए। मत्स्य विभाग ने तोपचांची के किशोर केवट को मालवाहक वैन और पांच लाभुकों को मत्स्य विपणन किट दी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्या नमकीन भंडार को 25 लाख, सुखदेव उज्ज्वल फूड प्रोडक्ट को 19 लाख और वैष्णवी एंटरप्राइजेज को 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। वहीं, अनुकंपा के आधार पर चयनित चार अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आठ कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और जन वितरण प्रणाली के कर्मियों के साथ खेल, क्विज, निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह में डीडीसी सन्नी राज, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

भुरकुंडा से अगवा कारोबारी सकुशल मुक्त, पांच गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

रामगढ़। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा बाजार में दिनदहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिए जाने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गई थी। अपराधियों ने गणेश ज्वेलर्स के समीप से कमलेश ठाकुर उर्फ दिनेश शर्मा (42 वर्ष) को मारपीट करते हुए सफेद रंग की स्विफ्ट कार में जबरन बैठा लिया और फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद किया, बल्कि वारदात में शामिल पांच आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में रांची जिले के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़, लक्ष्मी नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार साव (31), सहदेव नगर , ओटीसी मैदान निवासी राजमणि गुप्ता उर्फ बंटी (37), पंडरा निवासी रोशन कुमार सिंह (30) और घनश्याम सिंह (43)



शामिल हैं। वहीं, पांचवां आरोपित पीयूष कुमार (21) रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र अंतर्गत रसदा गांव का निवासी है।पुलिस ने आरोपितों के पास से अपहरण में प्रयुक्त सफेद रंग की स्विफ्ट कार के अलावा चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पतरातु एसडीपीओ राघवेंद्र शर्मा ने बुधवार को बताया कि वारदात 23 नवंबर की शाम करीब चार से पांच बजे के बीच भुरकुंडा बाजार में हुई। इस संबंध में अपहृत की पत्नी रिंकू देवी ने भुरकुंडा ओपी में कांड संख्या 307/2026 दर्ज कराया था।

एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण अपहरणकर्ता अपहृत कमलेश ठाकुर को रांची के पिठोरिया जंगल के समीप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल उन्हें सकुशल बरामद कर लिया।

इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 नवंबर की रात रांची रिंग रोड स्थित मां कॉलेज (होसिर) के समीप घेराबंदी की। यहां से अपहरण की घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार जेएच 01 सीवी-4472) के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया ।

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद और आपसी रंजिश की बात सामने आई है। इसी विवाद के कारण आरोपितों ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से रांची से भुरकुंडा बाजार तक पीछा कर कमलेश ठाकुर का अपहरण किया था। इसके बाद उरीमारी, बड़कागांव, केरेडारी और टंडवा होते हुए उसे गुमला ले जाकर मारपीट की। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित रोशन कुमार सिंह का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ एटीएस थाना कांड संख्या 04/24, दिनांक 3 जुलाई 2024 का मामला दर्ज होने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है।

राहुल दुबे गैंग के शूटर आनंद कुमार का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

बिभा संवाददाता

चतरा। राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ टंडवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के शूटर आनंद कुमार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बुधवार अहले सुबह थाना क्षेत्र के होन्हे गोड़वार जंगल में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आनंद कुमार के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और दो खोखा बरामद किया है।

इस संबंध में चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि बीते 11 नवंबर को संदारी की मांग को लेकर टंडवा थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली परियोजना की एवीएस ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के साइट ऑफिस पर गोलीबारी की घटना हुई थी। मामले के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पूछताछ के लिए चतरा निवासी आनंद कुमार को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उसने आम्रपाली परियोजना स्थित एवीएस कंपनी के कार्यालय में फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही हजारीबाग के एक होटल में हुई गोलीबारी में भी शामिल होने की बात बताई।

एसपी के अनुसार, घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए आनंद कुमार को उसके बताए स्थान होन्हे जंगल ले जाया गया था। वहां छिपाकर रखे हथियार को निकालने के बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। जिसमें आनंद कुमार के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी की ओर से दो और पुलिस की ओर से तीन राउंड गोली चलने की बात बताई गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आनंद कुमार ने गोलीबारी की घटनाओं में शामिल अन्य सहयोगियों के नामों का भी खुलासा किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार, टंडवा थाना प्रभारी विपिन कुमार, प्रशांत मिश्रा, प्रभात कुमार, मदन सिंह समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

मशीनों से कोयला लोडिंग के विरोध में मजदूरों ने किया प्रदर्शन

बिभा संवाददाता

गोड्डा। ईसीएल की राजमहल परियोजना अंतर्गत मोंटे कार्लो की ओर से संचालित हुर्रा-सी ओपन कास्ट परियोजना में डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) के कोयला लोडिंग कार्य में मशीनों के इस्तेमाल को लेकर मजदूरों का आक्रोश सामने आया है। मजदूरों ने पारंपरिक रूप से हाथों से किए जाने वाले कोयला लोडिंग कार्य को मशीनों के माध्यम से कराए जाने का विरोध करते हुए इसे उनकी रोजी-रोटी पर हमला बताया है।

बुधवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूर परियोजना के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए और मशीनों के माध्यम से कोयला लोडिंग की व्यवस्था बंद कर पूर्व की तरह मजदूरों से काम कराने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना था कि वे लंबे समय से कोयला लोडिंग का कार्य कर दिहाड़ी मजदूरी प्राप्त करते थे। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता था। लेकिन अब कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर मजदूरों को काम से वंचित करते हुए मशीनों के जरिए कोयला लोडिंग कराई जा रही है।

मजदूरों ने आरोप लगाया कि काम की तलाश में वे रोजाना खदान पहुंचते हैं, लेकिन वहां घंटों इंतजार करने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता। इससे उनके सामने परिवार चलाने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उनका कहना था कि मशीनों के इस्तेमाल से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन इसका सीधा नुकसान उन सैकड़ों मजदूरों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी आजीविका इसी काम पर निर्भर है।

प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर परियोजना प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर सैकड़ों मजदूरों के हस्ताक्षर हैं। मजदूरों ने प्रबंधन से इस व्यवस्था पर तत्काल संज्ञान लेने और प्रभावित श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने की मांग की।

बाद में इस मामले को लेकर राजमहल एरिया के कार्मिक प्रबंधक के साथ मजदूरों की वार्ता हुई। वार्ता में एपीएम मनोज ई. टुडू, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सोनेलाल टुडू सहित अन्य मजदूर नेता उपस्थित थे। वार्ता के दौरान मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की शर्त पर सहमति बनने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि मजदूरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों के अनुरूप व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिला तो वे आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में मुकेश लोहार, अनिल लोहार, मुकेश मढैया, संजय लोहार, जीतन हांसदा, सिकंदर सोरेन सहित सैकड़ों मजदूर शामिल हैं।

आसनसोल मंडल ने मनाया विश्व धरोहर सप्ताह, विद्यार्थियों को भारतीय रेल की गौरवशाली विरासत से कराया परिचित

बिहान भारत

आसनसोलः पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने विश्व धरोहर सप्ताह (19 से 25 नवंबर) के तहत 25 नवंबर को पूर्व रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आसनसोल में विशेष विरासत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मंडल के पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय रेल की समृद्ध ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत से परिचित कराना तथा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आसनसोल मंडल की ऐतिहासिक इमारतों और रेल विरासत को दर्शाने वाला विशेष धरोहर पोस्टर रहा। इस पोस्टर में बर्लिंगटन, आसनसोल स्टेशन, पूर्व रेलवे



उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (आसनसोल), सुभाष इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन इंस्टीट्यूट, डूरंड इंस्टीट्यूट, टैगोर इंस्टीट्यूट तथा विरासत रेल इंजन तिलोत्तमा को प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों को इन धरोहरों के महत्व और क्षेत्र में भारतीय रेल के विकास में उनके योगदान के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ये ऐतिहासिक भवन और संरचनाएं आज भी रेलवे की परंपराओं, स्मृतियों और गौरवशाली पहचान को संजोए हुए हैं। आसनसोल मंडल का लक्ष्य युवा पीढ़ी में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति गर्व, सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित करना है, ताकि वे अतीत से जुड़ते हुए एक प्रगतिशील और सतत भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित हो सकें। रेलवे के अनुसार, मंडल आधारभूत संरचना के विकास, तकनीकी आधुनिकीकरण और बेहतर यात्री सेवाओं के साथ-साथ अपनी समृद्ध रेल विरासत के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राज्यपाल से की मुलाकात, सम्मान फाउंडेशन कंपनी की उच्चस्तरीय जांच की मांग

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। राज्यभर में कार्यरत 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, श्रमिक अधिकारों के हनन, वेतन भुगतान में अनियमितता एवं एम्बुलेंस सेवा के संचालन में बरती जा रही लापरवाही से अवगत कराया गया।

संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सम्मान फाउंडेशन कंपनी की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग किए। संघ ने राज्यपाल को अवगत कराया कि फरवरी 2025 से अब तक कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है।

ईपीएफ एवं ईएसआई में अनियमितताओं और मनमानी की गई है। राज्यभर में लगभग 150 से 170 एम्बुलेंस लंबे समय से खराब पड़ी हैं, इसके वजह से 600 से 680 कर्मचारी ड्यूटी से वंचित हैं। संघ ने बताया कि अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2026 का वेतन भी नही मिला है।

कंपनी की ओर से वेतन भुगतान के



नाम पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जाए। खराब एम्बुलेंस के संचालन के नाम पर सरकारी भुगतान प्राप्त करने से संबंधित मामलों की जांच की मांग भी उठाई गई।

संघ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग 25 मई 2026 को सम्मान फाउंडेशन कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया था। बावजूद इसके कंपनी से अब तक एम्बुलेंस सेवा का संचालन कराया जा रहा है।

संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए, बकाया वेतन एवं अन्य देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, वंचित कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम पर लगाया जाए, कंपनी की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई।

इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी दिन-रात जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। संघ कर्मचारियों को न्याय दिलाने एवं उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित कराने के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा।

इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, धनबाद जिला सचिव रविंद्र कुमार शर्मा, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ-भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी सह प्रदेश मंत्री रमाशंकर प्रसाद, रांची जिला मंत्री सुबोध कुमार यादव एवं विकास तिवारी उपस्थित रहे।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट,भोसले गली,हरिहर सिंह रोड,बरियातू,रांची-834009(झारखंड) दूरभाषः 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा डी बी कॉर्प लिमिटेड ,प्लॉट नंबर- 535 व 1272, नियर फारेस्ट ऑफिस, ललगुटवा, रांची - 835303, झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू**(*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली** ।
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com